सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
YouTube
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023
www.newsparivahan.com
परिवहन विशेष
वर्ष 02, अंक 267, नई दिल्ली । शुक्रवार, 13 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 महिला सम्मान योजना की घोषणा दिल्ली विधानसभा चुनाव में बनेगी गेम चेंजर
06 कक्षाओं में परिवर्तन:राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-संरेखित शिक्षा
08 अमरदा एयर पोर्ट होगा की नहीं होगा साधारण लोगों की मन में आशंका

दिल्ली परिवहन विभाग ने राजपत्र अधिसूचना जारी कर किया एसटीए बोर्ड का गठन

संजय बाटला

नई दिल्ली। परिवहन विभाग द्वारा नई स्कीम, पालिसी और नियंत्रण संबंधित नए नियमो को लागू करने के लिए एसटीए बोर्ड में फैसला लेने अनिवार्य है। दिल्ली में कोरोना वायरस (2020) के आने से अब तक नए बोर्ड का गठन नही किया गया था और सभी आदेश परिवहन आयुक्त अपनी इच्छा से जारी करते आ रहे थे पर अब दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा एसटीए बोर्ड का गठन कर उसकी राजपत्र अधिसूचना भी जारी कर दी।

परिवहन विभाग द्वारा अनगिनत वर्षों के बाद एसटीए बोर्ड में किसी विधायक को एसटीए बोर्ड का सदस्य मनोनीत करने की जगह एक्सपर्ट्स को एसटीए बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया।

दिल्ली की जनता को नए वाहनों के नियमों को बनाने में सक्षम एसटीए बोर्ड में एक्सपर्ट्स के होने से फायदा मिल सकता है पर आज की तारीख़ में कार्यरत परिवहन आयुक्त के रहते जनहित में निर्णय और नए नियम आने में संदेह है क्योंकि परिवहन आयुक्त द्वारा अपने कार्यकाल में अभी तक जारी सभी आदेश जनता के हित की जगह सरकारी राजस्व इजाफा करवाने में देखने को मिले।

(आप सभी की जानकारी हेतु राजपत्र अधिसूचना सलग्न)।

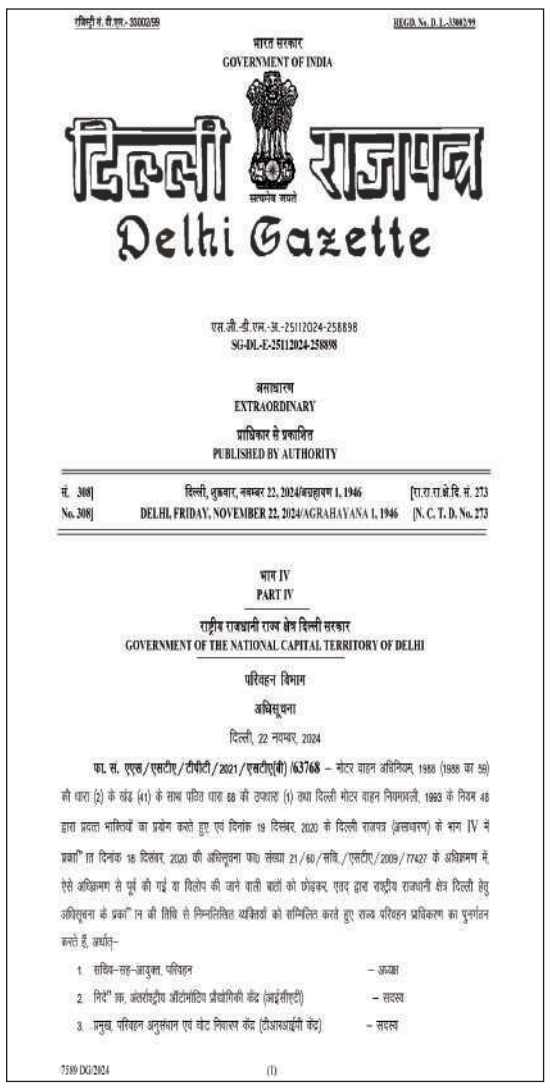

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25112024-258898
SG-DL-E-25112024-258898

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308] दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 2024/अग्रहायण 1, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 273
No. 308] DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 2024/AGRAHAYANA 1, 1946 [N. C. T. D. No. 273

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 नवम्बर, 2024

फा. सं. एएस/एसटीए/टीपीटी/2021/एसटीए(बी)/63768 – मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा (2) के खंड (41) के साथ पठित धारा 68 की उपधारा (1) तथा दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं दिनांक 19 दिसंबर, 2020 के दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग IV में प्रकाशित दिनांक 18 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना फा0 संख्या 21/60/सचि./एसटीए/2009/77427 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण का पुनर्गठन करते हैं, अर्थात्–

1. सचिव-सह-आयुक्त, परिवहन – अध्यक्ष
2. निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीएटी) – सदस्य
3. प्रमुख, परिवहन अनुसंधान एवं चोट निवारण केंद्र (टीआरआईपी केंद्र) – सदस्य

7589 DG/2024 (1)

2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY [PART IV]

4. विशेष आयुक्त, पुलिस, यातायात – सदस्य
5. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण – सदस्य-सचिव

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
राकेश शर्मा, उप -सचिव(परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 22nd November, 2024

No. AS/STA /TPT/2021/STA(B)/ 63768 - In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 68 read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988, (59 of 1988) and rule 48 of the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 and in supersession of notification no. F 21/60/Secy/STA/2009/77427 dated 18th December, 2020, published in Part-IV of Delhi Gazette (Extra Ordinary) dated the 19th December, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the State Transport Authority for the National Capital Territory of Delhi is hereby reconstituted, consisting of the following persons with effect from the date of publication of notification, namely:-

1. Secretary-cum-Commissioner, Transport	Chairperson
2. Director, International Centre for Automotive Technology (ICAT)	Member
3. Head, Transportation Research & Injury Prevention Center (TRIP center)	Member
4. Special Commissioner of Police, Traffic	Member
5. Secretary, State Transport Authority	Member-Secretary

This issues with the approval of Hon'ble LG , Government of NCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
RAKESH SHARMA, Dy. Secy. (Transport)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

दिल्ली के व्यवसायिक वाहनों के मालिको ने वाहन जांच में आ रही परेशानियों से वीरेंद्र सचदेवा को अवगत करवा कर मदद की गुहार लगाई

संजय बाटला

नई दिल्ली। अभिमन्यु त्यागी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली के वाहन मालिकों/चालकों और कारोबारियों ने दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से मुलाकात कर परिवहन आयुक्त द्वारा बिना सोचे समझे और बिना पूर्ण जानकारी प्राप्त किए जारी आदेश से दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिकों और कारोबारियों को आ रही परेशानियों से अवगत करवाया और उनसे इसके लिए जल्द से जल्द समाधान निकलवाने की गुहार लगाई।

इस मुलाकात में अभिमन्यु त्यागी के साथ केके छाबड़ा, राजू कक्कड़, विनोद नेगी, देवेंद्र यादव और सुभाष त्यागी उपस्थित थे। 20 मिनिट की इस मुलाकात में अभिमन्यु ने सचदेवा को बताया

1. झूलझूली वाहन जांच शाखा में इतने वाहनों को जांच करने की क्षमता ही नहीं है जितने वाहनों को वहां वाहन जांच के आदेश जारी किए गए

2. झूलझूली वाहन जांच शाखा में वाहन मालिकों/ चालकों और वाहनों की सुरक्षा भी नहीं है जिसके बारे मे दिल्ली पुलिस तक को जानकारी है

3. झूलझूली वाहन जांच शाखा में परिवहन अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जान सुरक्षित नहीं है जिस कारण काई अधिकारी वीआरएस तक दे चुके है और परिवहन विभाग द्वारा 2 एफआईआर भी दर्ज करवाई जा चुकी हैं

4. झूलझूली वाहन जांच शाखा में जिस कंपनी द्वारा एटीएस संयंत्र लगाया हुआ है उसका टेंडर खत्म हुए काफ़ी समय हो चुका है और परिवहन आयुक्त द्वारा बार बार एक्टेंशन मिलने प्राप्त कर के काम कर रही हैं ।

5. बुराड़ी वाहन जांच शाखा में अनगिनत एटीएस संयंत्र और उसके चलने के लिए आवश्यक पूरा सिस्टम उपलब्ध है फिर भी परिवहन आयुक्त उसको शुरू करवाने की जगह झूलझूली वाहन जांच शाखा में कार्यरत कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से एक्सटेंशन देकर क्षमता से अधिक वाहनों को वहां भेजकर वाहन मालिकों को परेशानियों में धकेल रहे है

6. आज दिल्ली के व्यवसायिक वाहनों को परिवहन आयुक्त द्वारा जारी इस आदेश के कारण वाहन जांच की अपॉइंटमेंट तक भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और बिना वाहन जांच प्रमाण पत्र के सड़को पर वाहन नहीं चला पा रहे और जुर्माने के साथ भुखमरी के कगार पर पहुंचाते जा रहे है।

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सभी तथ्यों को सुनने और सबूतों के साथ समझने के बाद 15 दिन के अंदर ही इस समस्या का समाधान करवाने का वायदा दिया।

दिल्ली के इस इलाके से हटाया जाएगा ट्रैफिक सिग्नल, लोगों को जाम से मिलेगा छुटकारा

परिवहन विशेष न्यूज

विकास मार्ग पर लगने वाले जाम से यात्रियों को जल्द ही निजात मिलेगी। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से कड़कड़ी मोड़ क्षेत्र के बीच करीब 2.5 किमी लंबे मार्ग पर निर्माण विहार व प्रीत विहार ट्रैफिक सिग्नल को खत्म कर यू-टर्न बनाए जाएंगे। इसके हो जाने के बाद वाहनों का जाम नहीं लगेगा और यातायात सुचारू रूप से चलेगा।

नई दिल्ली। विकास मार्ग से जाम समाप्त करने और सुरक्षित यातायात के लिए लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन (laxmi nagar metro station) क्षेत्र से कड़कड़ी मोड़ क्षेत्र के बीच दिल्ली मेट्रो लाइन (Delhi metro line) के नीचे करीब 2.5 किमी लंबे मार्ग पर निर्माण विहार व प्रीत विहार ट्रैफिक सिग्नल को खत्म करने की तैयारी है।

तीन लेन के इस मार्ग पर प्रतिदिन खरीददारी के लिए आने वाले हजारों लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिए उपलब्ध सीमित स्थान के कारण वाहन मुख्य मार्ग पर ही पार्क कर दिए जाते हैं, जिससे यातायात आवागमन प्रभावित रहता है।

विभाग जल्द ही परीक्षण करेगा शुरू

साथ ही कुछ-कुछ सौ मीटर दूरी पर ही ट्रैफिक सिग्नल्स के कारण रुके वाहन यातायात प्रवाह को बाधित करते रहते हैं, जो व्यस्त समय में भीषण जाम में परिवर्तित हो जाता है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को इसकी योजना साझा की गई, विभाग जल्द ही इसपर परीक्षण शुरू करेगा।

अगस्त व नवंबर माह में यातायात पुलिस (Delhi traffic police) उपायुक्त सहित सहायक आयुक्त पुलिस व यातायात निरीक्षक के साथ विकास मार्ग पर साझा निरीक्षण करने के बाद इस योजना को पीडब्ल्यूडी से साझा किया गया है। इस मार्ग पर अनेक आवासीय क्षेत्र होने के साथ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर से संबंधित काफी दुकानें हैं।

यहां विभिन्न कंपनियों को शोरूम, माल, मेट्रो स्टेशन, सरकारी कार्यालय आदि हैं। यहां हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन खरीदारी के लिए आते हैं। यह मार्ग पूर्वी दिल्ली के महत्वपूर्ण भागों को दिल्ली के मध्य भाग से जोड़ता है। इसमें बीच-बीच में कई मार्ग भी जुड़ते हैं।

सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपराध की घटनाओं में भी होता है इजाफा

इसलिए यातायात का दबाव इस मार्ग पर काफी रहता है। इस मार्ग पर दिनभर लगने वाले जाम के कारण समय, ईंधन बर्बाद होने के साथ प्रदूषण भी बढ़ता है। सड़क दुर्घटनाएं और अपराध की घटनाएं भी होती हैं।

योजना के तहत इस मार्ग पर ट्रैफिक सिग्नल वाले तीराहे व चौराहों को बंद कर बीच बीच में यूटर्न बनाया जाएगा। यूटर्न के कारण वाहनों का जाम न लगे, इसके लिए हर यूटर्न के पास आफसेट यानी यूटर्न से पहले सेंट्रल वर्ज से रोड पर तीन से चार फीट करीब 20-30 मीटर हिस्सा को बैरिकेट किया जाएगा।

इससे सीधे निकलने वाले वाहन यू-टर्न ले रहे वाहनों में मिलेंगे नहीं। इससे यू-टर्न के लिए वाहनों को जगह मिल जाएगी। ये यू-टर्न बंद किए गए डिवाइडर से लगभग 150 आगे और पीछे बनाने की योजना है। इससे आसपास के इलाके में जाने वाले वाहन चालकों को भी सुविधा होगी और याायात रूकेगा नहीं।

इन सभी यूटर्न पर ऊंचाई नियंत्रण उपकरण भी लगाया जाएगा ताकि बड़े वाहन इसमें प्रवेश न करें। सुरक्षित यातायात के लिए यहां पर्याप्त मात्रा में सड़क सुरक्षा उपकरण जैसे, रिफ्लैक्टर्स, ब्लिंकर्स, संकेतक, पेंट मार्किंग, गति नियंत्रक की व्यवस्था की जाएगी। यह प्रस्ताव एनजीओ गुरू हनुमान सोसाइटी ऑफ भारत ने तैयार किया है।

एनजीओ के महासचिव अतुल रणजीत कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत पांच ट्रैफिक सिग्नल को खत्म करना है। फिलहाल इसे पहले चरण में दो ट्रैफिक सिग्नल खत्म करने की तैयारी है। इससे विकास मार्ग पर प्रतिदिन के जाम से राहत पाने में मदद मिलेगी।

पूर्वी रेंज जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रावल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा गया है। प्रीत विहार और निर्माण विहार की लाल बत्ती खत्म कर दी जाएगी, उनकी जगह दो यू-टर्न बनाएं जाएंगे। कड़कड़ी मोड़ के बाद लक्ष्मी नगर लाल बत्ती पड़ेगी। जाम खत्म करने के लिए यह कवायद की जा रही है।

'वायु प्रदूषण के प्रतिबंधों में ढील दें, पूरे साल आतिशबाजी पर लगे बैन', सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज

जस्टिस अभय एस. ओका और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने गुरुवार को वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों (हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान) से कहा कि वे अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें। साथ ही केंद्र सरकार सीक्यूएएम में विशेषज्ञों के तौर पर पर्यावरण कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्रों के एक्सपर्ट को सलाहकार के तौर पर नियुक्त करें।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले पर कहा कि वायु प्रदूषण के स्टेज-2 से निपटने के लिए ग्रेप-4 के प्रतिबंधों में ढील दें और इसे अगले आदेश तक जारी रखें। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों से पूरे साल पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बारे में अंतिम फैसला लेने को कहा।

जस्टिस अभय एस. ओका और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने गुरुवार को वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और अन्य एनसीआर राज्यों (हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान) से कहा कि वे अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें। साथ ही केंद्र सरकार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएएम) में विशेषज्ञों के तौर पर पर्यावरण, कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्रों के सर्वोच्च विशेषज्ञों को सलाहकार के स्तर पर नियुक्त करें।

ग्रेप पर पिछला आदेश जारी रहेगा: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) पर उसका पिछला आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा और साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएएम) को दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए संशोधित उपायों के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए, इसने यह भी सुझाव दिया कि सरकारी विभागों को इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग शुरू करना चाहिए।

पीठ ने कहा कि न केवल वायु प्रदूषण बल्कि ध्वनि प्रदूषण पर भी रोक लगाने के लिए प्रतिबंध की आवश्यकता है। इसने नोट किया कि एनसीआर राज्यों में पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध के मुद्दे को अभी तक संबोधित नहीं किया गया है।

पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर राज्य फैसले लें: सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने कहा, ₹हम संबंधित राज्य सरकारों को पूरे साल पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बारे में अपने फैसले पेश करने का निर्देश देते हैं।₹ शीर्ष अदालत ने कहा कि जब वह पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है, तो इसमें उनके निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध भी शामिल होगा। इस पर दिल्ली सरकार ने खंडपीठ को बताया कि जनवरी तक पटाखों पर प्रतिबंध लागू है। वह जल्द ही पूरे साल प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

सड़क हादसों पर बोले नितिन गडकरी; लेन की अनुशासनहीनता बड़ा कारण, खुद की कार का दो बार हुआ चालान

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में गुरुवार को सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार के असफल प्रयासों को निस्संकोच स्वीकारा। इस दौरान उन्होंने कहा कि लेन की अनुशासनहीनता हादसों का बड़ा कारण है। इसके साथ ही उन्होंने नियमों की अनदेखी को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि उनका खुद का दो बार चालान कट चुका है।

नई दिल्ली। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार के असफल प्रयासों की पीड़ा गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की निस्संकोच स्वीकोरोक्ति के रूप में सामने आई। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गडकरी ने बेबाकी से कहा कि जब वह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में विदेश जाते हैं और सड़क हादसों पर चर्चा होती है तो हाथों से अपना मुंह छिपाने का प्रयास करते हैं।

सड़क हादसों का प्रमुख कारण

लेन की अनुशासनहीनता को सड़क हादसों का प्रमुख कारण बताते हुए उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जब उन्होंने कार्यभार संभाला था, तब हादसों को पचास प्रतिशत घटाने का लक्ष्य तय किया था। आज हादसे घटने की बात तो भूल जाइए, यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि सड़क हादसों की संख्या बढ़ गई है।

दो बार मुंबई में चालान कटा

नितिन गडकरी ने यातायात नियमों की अनदेखी पर चिंता जताते हुए अपना उदाहरण भी दिया कि उनकी कार का भी दो बार मुंबई में चालान हो चुका है। उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि दुनिया में लोग तेज गाड़ी ही चला रहे हैं। भारत में बड़ी समस्या लेन का अनुशासन न होने से है। यातायात नियमों के प्रति मानव व्यवहार और समाज के बदलाव पर जोर देते हुए मंत्री ने बताया कि उनका स्वयं का परिवार भी सड़क हादसे का शिकार हुआ था, तब उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था।

सड़क हादसे को लेकर शेयर किया अनुभव

सड़क हादसे को लेकर व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क पर ट्रकों की पार्किंग और ट्रकों द्वारा लेन का पालन न किए जाने से भी बहुत हादसे होते हैं। मंत्री ने अधिक सड़क हादसे वाले राज्यों का ब्योरा भी सदन में प्रस्तुत किया।

2019 से 2022 के बीच कितने हुए सड़क हादसे

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MoRTH के मुताबिक, साल 2019 से 2022 के बीच भारत में 1.21 लाख से ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं। 2022 में सबसे ज्यादा हादसे साल 2022 में हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, 2019 में 33602, 2020 में 26541 हादसे हुए। साल 2021 के दौरान भी कोरोना के कारण हादसों में कमी दर्ज की गई लेकिन फिर भी 28934 हादसे हुए। 2022 में यह संख्या बढ़कर 34262 हो गई।

हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंचा था सभी का पसंदीदा मोमोज, दिलचस्प है इसकी कहानी

भारत में मोमोज लोगों का पसंदीदा बन चुका है। इसे साथ खाई जाने वाली चटनी इतनी तीखी और चटपटी होती है क ि ये मोमोज के स्वाद में तड़का लगा देती है। भारत में मोमोल 1970-80 के दौरान आया था। पहले तो इसे स र्फि स्टीम करके परोसा जाता था लेक नि आज ये कई वैरायटीज में उपलब्ध है।

नई दिल्ली। हम इंडियंस में मोमोज का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। भारत में मोमोज ने एक खास पहचान बना ली है। इस देश में जब भी स्ट्रीट फूड का नाम लिया जाता है तो मोमोज का नाम सबसे पहले आता है। ये एक ऐसा स्नैक है जो हर उम्र के लोगों को बेहद पसंद आता है। पहले तो मोमोज सिर्फ भाप में पकाकर तैयार किया जाता था लेकिन आज ये कई वैरायटी में खाया जाता है। फ्राइड, तंदूरी, चॉकलेट, केएफसी स्टाइल मोमोज हर किसी को बेहद पसंद आ रहे हैं। अब तो गली-नुक्कड़ से लेकर छोटे-बड़े रेस्टोरेंट्स, हर जगह ये आसानी से मिल जाता है। इसकी तीखी चटनी लोगों को मोमोज का दीवाना बना रही है।

तीखी चटनी की वजह से ही मोमोज को भारत (Momo Trend In India) में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल हुई है। हालांकि भारत में मोमोज के आने का सफर इतना आसान नहीं था। ये डिश भले ही तिब्बत और नेपाल से हमें मिली है लेकिन आज ये भारत (Momo History In India) की शान बन चुका है। इसे मशहूर बनाने में सोशल मीडिया और फूड ब्लॉगर्स ने भी अहम भूमिका निभाई है। आइए विस्तार से जानते हैं मोमोज के भारत आने की दिलचस्प कहानी क्या है और क्यों यहां के लोगों में इसका क्रेज इतना बढ़ गया।

पहाड़ों से शुरू होती है मोमोज की कहानी

भारत में मोमोज सिर्फ एक स्नैक ही नहीं बल्कि फीलिंग बन गया है। यहां पर मोमोज का बढ़ता क्रेज इस बात का प्रतीक है कि कैसे भारत अलग-अलग संस्कृतियों को आसानी से अपनाता चला आ रहा है। भारत में अपनी धाक जमाने के लिए मोमोज को काफी लंबा सफर तय करना पड़ा था। इसकी कहानी पहाड़ों से शुरू होती है। मोमोज तिब्बत चाइना, नेपाल और भूटान जैसे देशों में खाया जाने वाला प्रमुख व्यंजन था।

1970-80 में मोमोज ने भारत में बनाई पहचान

तिब्बतियों और नेपालियों को ख्याल आया कि क्यों न इस रेसिपी को भारत लाया जाए। इंडिया में सबसे पहले मोमोज उत्तर-पूर्वी राज्यों में पहुंचा। जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल हैं। वहां के लोगों को मोमोज काफी पसंद आया। धीरे-धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। इसके बाद ये दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में आ पहुंचा। 1970-80 की बात है जब मोमोज ने भारत में (Momo Evolution In India) अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी।

कैसे बढ़ा मोमोज का ट्रेंड

मोमोज को लोगों का पसंदीदा बनाने में सबसे बड़ा हाथ इसके साथ खाई जाने वाली लाल और तीखी चटनी का ही है। क्योंकि भारत में आधे से ज्यादा आबादी तीखा और चटपटा खाना पसंद करती है। इसके मशहूर होने की एक वजह ये भी है कि ये काफी सस्ते मिलते हैं। मोमोज को बनाने में ज्यादा सामग्री या समय भी नहीं लगता है। आटा, सब्जियां या मांस और कुछ मसालों से इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसीलिए ज्यादातर ठेले वाले इसे बनाते हैं। इसकी उनकी इनकम भी बढ़ रही है।

हर मौसम में लोगों को पसंद आता है मोमोज

पहले मोमोज को सिर्फ स्टीम या फ्राई करके ही बनाया जाता था जिसमें हरी सब्जियों की स्टफिंग होती थी। लेकिन अब पनीर, चिकन, मटन, कॉर्न की फिलिंग भी होने लगी है। तंदूरी मोमोज तो आजकल हर जगह छाए हुए हैं। सोशल मीडिया और फूड ब्लॉगर्स ने भी मोमोज को मशहूर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सर्दी हो या गर्मी-बरसात, मोमोज हर मौसम में लोगों का पसंददीदा बन चुका है।

भारत में अब इन वैरायटीज में मिलते हैं मोमोज

- स्टीम्ड मोमोज
- फ्राइड मोमोज
- करारे मोमोज
- चीजी मोमोज
- चॉकलेट मोमोज
- कोरियन मोमोज
- ग्रेवी मोमोज
- तंदूरी मोमोज
- मंचूरियन मोमोज

सर्दियों में घटाना है वजन, तो रोज सुबह गर्म पानी में मिलाकर पिएं नींबू; मिलेंगे कई बेमिसाल फायदे

सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने आपकी सेहत के लिए कई मायनों में फायदेमंद होता है। क्या आप जानते हैं कि अगर गर्म पानी में नींबू मिला दिया जाए तो फायदे दोगुने हो जाते हैं। इससे न सिर्फ वजन घटाने में मदद मिलेगी बल्कि इम्युनिटी भी बूस्ट होगी। आइए जानते हैं गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीने के फायदे।

नई दिल्ली। सर्दियों में लोग अक्सर हेल्दी रहने और खुद को ठंड से बचाने के लिए कई सारे उपाय करते हैं। सर्दी के दिनों अक्सर लोग अपने दिन की शुरुआत हल्के गर्म पानी के साथ करते हैं। सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीना सेहत के लिए कई मायनों में फायदेमंद होता है। इससे सेहत से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही यह वेट लॉस में भी मदद करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इस गुनगुने पानी में आप नींबू (Winter lemon water benefits) मिला देंगे, तो इससे होने वाले फायदे दोगुने हो जाते हैं।

रोज सुबह गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीने से कई हैरान करने वाले फायदे मिलते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे रोजाना गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीने से होने वाले ऐसे ही कुछ बेमिसाल फायदों के बारे में-

पाचन में मदद करे

गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीने से पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। नींबू का रस एसिडिक होता है, जो गैसट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करने में मदद करता है, जो खाना पचाने के लिए जरूरी है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के एक अध्ययन से पता चलता है कि बेहतर पाचन से सूजन और असुविधा जैसे अपच के लक्षणों को कम किया जा सकता है। ऐसे में गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीने से पाचन से जुड़ी समस्याओं के दूर करने में मदद मिलती है।

वेट कम करने में मददगार

अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो सुबह खाली पेट गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीने से सेहत को कई फायदे मिल सकते हैं। गर्म पानी और नींबू वेट मैनेजमेंट में मददगार होते हैं। नींबू में पेक्टिन फाइबर होता है, जो आपके पेट को भरा रखता है, जिससे आप ज्यादा खाने से बचते हैं। एपेटाइट में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि ज्यादा पानी पीने से भूख कम हो सकती है और वजन घटाने में फायदे हो सकता है।

इम्युनिटी बढ़ाए

सर्दियों में अक्सर इम्युनिटी कमजोर होने की वजह से कई बीमारियां और संक्रमण लोगों को अपना शिकार बना लेती हैं। ऐसे में गर्म पानी और नींबू पीने से इम्युनिटी बूस्ट करने में मदद मिलती है। दरअसल, नींबू में विटामिन-सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो इम्यून सिस्टम मजबूत करने में मदद करता है। शोध से भी पता चलता है कि विटामिन सी रेस्पिरेटरी संक्रमण की गंभीरता को कम कर सकता है।

मूड बेहतर करे

अगर आप गर्म और नींबू के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो इससे न सिर्फ आपका मूड बेहतर होता है, बल्कि आप दिनभर एनर्जी से भरपूर भी रहते हैं। पानी और नींबू में मौजूद विटामिन-सी का आपके मूड और एनर्जी को बेहतर कर सकता है।

स्किन को बनाए हेल्दी

नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, खासतौर पर विटामिन सी, स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करता है। एंटीऑक्सिडेंट ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने में मदद करते हैं, जिससे समय से पहले बुढ़ापा और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक अध्ययन में पाया गया कि विटामिन सी स्किन की ड्राईनेस और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है।

गडकरी बताएं दिल्ली-एनसीआर के लोग आखिर कहां जाएं

योगेंद्र योगी

देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली हर तरह के जानलेवा प्रदूषण की शिकार है। वाहनों और फैक्ट्री के धुएं से होने वाला प्रदूषण, यमुना का प्रदूषण और घरों-प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे का प्रदूषण। तीनों तरह के प्रदूषण का बोझ उठाने के लिए दिल्ली अभिशप्त हो चुकी है।

दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण से खराब हालात में सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रयास भी सरकारों के नाकारपन के कारण बौने साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट दर्जनों बार फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई दौरान कहा कि कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अदालत ने कहा कि सरकारी एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय की कमी है। साथ ही अदालत ने कहा कि दिल्ली में फिल्हाल ग्रैप-4 जारी रहेगा। दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीपीसीसी, सीएक्यूएम और अन्य अधिकारियों के बीच समन्वय की पूरी तरह से कमी है। समन्वय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पर है। इसलिए ग्रैप-4 को लागू करने के लिए समन्वय हो।

देश की राजधानी दिल्ली का प्रदूषण इतना खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली आने से घबराते हैं। गडकरी ने कहा कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडने से वे दिल्ली आने से कतराते हैं। गडकरी मंत्री हैं। उनके पास साधन और सुविधाएं हैं। वे कहीं भी आसानी से आवागमन कर सकते हैं। सवाल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र (एनसीआर) के करोड़ों लोगों के जीवन का है। इतने लोग अपना कामकाज, घरबार छोड़ कर कहां जाएं। प्रदूषण के धीमे जहर को पीना उनकी मजबूरी बन गई है। ज्यादातर सांसदों, मंत्रियों पर अकूत दौलत है। उनके लिए प्रदूषण से बचने के लिए कहीं भी देश में सरकारी खर्च पर आना-जाना आसान हैं। वैसे भी नेताओं को संसद और विधानसभा को सुचारू चलाने की ज्यादा ङ्कषचता नहीं है। दिल्ली और एनसीआर के लोगों को सरकारी मशीनरी और नेताओं के नाकारपन का अभिशाप झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है।

देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली हर तरह के जानलेवा प्रदूषण की शिकार है। वाहनों और फैक्ट्री के धुएं से होने वाला प्रदूषण, यमुना का प्रदूषण और घरों-प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे का प्रदूषण। तीनों तरह के प्रदूषण का बोझ उठाने के लिए दिल्ली अभिशप्त हो चुकी है। दिल्ली में केंद्र भाजपा गठबंधन की और राज्य में आप की सरकार मौजूद हैं। इससे पहले दिल्ली में लंबी अवधि तक कांग्रेस का शासन रहा है। प्रदूषण से निपटने में सभी राजनीतिक दल नाकाम रहे हैं। दिल्ली में कचरे का पहाड़ आज भी नेताओं के दावों-वादों को मुंह चिढ़ा रहा है। हिंदू-मुस्लिम विवाद और भ्रष्टाचार की तरह प्रदूषण नेताओं के लिए कभी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। जब कभी प्रदूषण का मुद्दा उठता भी है तो केंद्र और दिल्ली की सरकार गेंद एक-दूसरे के पाले में डाल कर अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाती हैं। यही वजह है कि दिल्ली और एनसीआर की आबोहवा इतनी बिगड़ चुकी है कि सांस लेना भी दुभर हो रहा है।

विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले कम से कम १० सिगरेट जितना प्रदूषण हर दिन लेने को विवश हैं। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जैसी संवैधानिक स्वतंत्र संस्थाए भी तमाम प्रयासों के बावजूद दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण से निपटने में प्रभावी भूमिका अदा नहीं कर सकी। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अपने बयान में स्वीकार किया था कि दिल्ली में ५० प्रतिशत प्रदूषण वाहनों से निकलता है। गडकरी देश के परिवहन मंत्री हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर प्रदूषण की विकराल समस्या से निपटने की जिम्मेदार किसकी है। जब देश का परिवहन मंत्री ही समस्या के समाधान से मुंह चुराने लगे तो अवाम किससे उम्मीद करे।

स्विस संगठन की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दिल्ली को सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला राजधानी शहर बताया गया है। रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 2023 में 134 देशों में से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद भारत की वायु गुणवत्ता तीसरी सबसे खराब की भविष्यवाणी की गई। राष्ट्रीय राजधानी को वर्ष 2018 से लगातार चार बार विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि अनुमान है कि भारत में 1.36 अरब लोग पीएम 2.5 की सांद्रता का अनुभव करते हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अनुशंसित वार्षिक दिशानिर्देश स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक है।

दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण से खराब हालात में सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रयास भी सरकारों के नाकारपन के कारण बौने साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट दर्जनों बार फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई दौरान कहा कि कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अदालत ने कहा कि सरकारी एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय की कमी है। साथ ही अदालत ने कहा कि दिल्ली में फिल्हाल ग्रैप-4 जारी रहेगा। दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीपीसीसी, सीएक्यूएम और अन्य अधिकारियों के बीच समन्वय की पूरी तरह से कमी है। समन्वय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पर है। इसलिए ग्रैप-4 को लागू करने के लिए समन्वय हो।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को फटकार लगाई क्योंकि राज्य प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू करने में विफल रहे। यह ऐसे समय में हुआ है जब दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता बहुत खराब बनी हुई है, जिससे सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। मामले की सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत की पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा खेतों में लगी आग को बुझाने के प्रयासों को मात्र दिखावा करार दिया। हवा की गुणवत्ता खराब होने का एक स्पष्ट कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों में पराली जलाने की बार-बार होने वाली घटनाएँ हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर को पर्यावरण कानूनों को शक्तिहीन बनाने के लिए केंद्र की आलोचना की और कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) अधिनियम के तहत पराली जलाने पर दंड से संबंधित प्रावधानो को लागू नहीं किया गया है। मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के प्रावधान को लागू करने के लिए कोई आवश्यक तंत्र बनाए बिना ही अधिनियम लागू कर दिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार भारत में हर साल पैदा होने वाले 22 मिलियन टन चावल के ठूंठ में से लगभग 14 मिलियन टन पराली को आग के हवाले कर दिया जाता है।

यह पैदा होने वाले चावल के ठूंठ का लगभग 63.6 प्रतिशत है और हरियाणा और पंजाब में अकेले जलाई जाने वाली पराली का 48 प्रतिशत हिस्सा है। हालत यह है कि वोटों के डर से राज्य और केंद्र की सरकारें पराली जलाने पर पूरी तरह रोक नहीं लगा पा रही हैं। राजनीतिक दलों के लिए किसानों का वोट बैंक आम लोगों के जीवन पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि पराली जलाने की हर साल होने वाले घटनाओं के बावजूद कोई भी सरकार सख्त कदम उठाने से हिचकिचाती है। यहां तक की सरकारें वोटों के लालच में लगातार अदालत के निर्देशों की अवहेलना कर रही हैं। कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने कथित तौर पर कैथल जिले में पराली जलाने के आरोप में 18 किसानों को गिरफ्तार किया था। ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने में विफल रहने के कारण राज्य के कृषि विभाग के करीब 24 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था। गौरतलब है कि हजारों किसान पराली हर साल जलाते हैं। इसके बावजूद कुछ किसानों की गिरफ्तारी महज दिखावा है। केंद्र सरकार ने 2022 में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर राज्यों में फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना शुरू की। पंजाब को पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए 2018-22 के दौरान इस योजना के तहत 1,387.6 करोड़ रुपये से अधिक मिले। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 22 अक्टूबर को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह बताए कि राज्य में धान की पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के लगातार प्रयासों के बावजूद प्रदूषण से बिगड़े हालात में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। दरअसल नौकरशाह नेताओं के इशारों पर काम करते हैं। नेता वोट के कारण किसानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से कतराते हैं। यह निश्चित है विश्व में प्रदूषण को लेकर बदनाम हो चुकी राजधानी के हालात सुधारने के लिए जब तक अदालतें नौकरशाहों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करेंगी, तब तक इनकी प्रवृत्ति में सुधार संभव नहीं है।

दिल्ली में ही लेना चाहते हैं सर्दियों का सारा मजा, तो जरूर करें दि विंटर ड्रीम कार्निवाल का दीदार

दिलवालों की दिल्ली के लिए शहर में आ रहा है दि विंटर ड्रीम कार्निवाल जहां आप न सिर्फ ठंड का मजा ले सकते हैं बल्कि अपने ही शहर में कदम अलग और अनोखा अनुभव भी ले सकते हैं। यह कार्निवल 28 और 29 दिसंबर 2024 को NSIC प्रदर्शनी मैदान होगा। जानते हैं क्यों खास है ये कार्निवल और इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी।

नई दिल्ली। सर्दियों में घूमने-फिरने का अपना अलग मजा होता है। खासकर अगर आप दिल्ली में हैं, तो यहां की सर्दियों की बात ही कुछ अलग है। दिल्ली की सर्दियों का जिक्र तो लंबे समय से चला आ रहा है। यहां इस मौसम में घूमने और एक्सप्लोर करने के कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इसी बीच ठंड का मजा दोगुना करने के लिए आपकी अपनी दिल्ली में आ रहा है द विंटर ड्रीम कार्निवल। यह आपके लिए एकदम अलग और अनोखा अनुभव होगा, जहां आप सर्दियों का दोगुना मजा ले सकेंगे। इस दिसंबर आपको बिना कहीं बाहर जाए, दिल्ली में ही हॉट एयर बैलून्स, स्टंट शोज, लाइव बॉक्सिंग मैचेज और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास कराने आ रहा है 'द विंटर ड्रीम कार्निवल'। 28 और 29 दिसंबर 2024 को NSIC प्रदर्शनी मैदान में होने वाला ये कार्निवल न सिर्फ पारंपरिक उत्सवों का जश्न मनाएगा, बल्कि कुछ ऐसे अद्भुत और अनोखे आकर्षण पेश करेगा, जो दर्शकों को रोमांच से भर देगा। आइए जानते हैं क्या है इस कार्निवल में खास-

हॉट एयर बैलून का अनुभव : दिल्ली में पहली बार, उत्सव आगंतुकों को गुब्बारों के रंग-बिरंगे जादू से रूबरू कराएगा, जहां वे इनके साथ सेल्फी ले सकेंगे और यादगार लम्हे बना सकेंगे।

हाई वोल्टेज स्टंट शोज : मन को झंझोर देने वाले स्टंट प्रदर्शन, जहां कुशल स्टंटमैन अपनी दिलचस्प कलाकारियों से आपकी सांसें थाम देंगे।

लाइव बॉक्सिंग मैचेज : उत्सव में पेशेवर बॉक्सर्स की भिड़ंत भी देखने को मिलेगी, जो अपने जोश और जुनून का प्रदर्शन करेंगे।

लेजर डांस और फैशन की रंगीनियां : इस दौरान नई टेक्नीक के साथ नृत्य की भव्य प्रस्तुतियाँ और फैशन परेड भी होंगी, जो आपको नए ट्रेंड्स से रूबरू कराएंगी।

धमाकेदार संगीत और DJ नाइट्स : इस कार्निकल में धूम मचाने वाले बैंड्स और DJ आपके लिए लाइव परफॉर्मेंस देंगे, जिनके गाने आपके पैरों को थिरकने पर मजबूर कर देंगे।

खास शॉपिंग और लाइफस्टाइल जोन : अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं, तो यह कार्निवल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित होगा। आपको यहां विभिन्न विक्रेताओं से अनूठे सामान खरीदने का मौका मिलेगा।

लजीज खाने की चाशनी : उत्सव में आपको खाने के लिए गौरमेट डिशेज से लेकर स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड तक सब कुछ मिलेगा।

ब्रांड्स के साथ साझेदारी : इस कार्निवल में अनेक प्रसिद्ध ब्रांड्स भी शामिल होंगे, जो इस उत्सव को और भी रोमांचक बनाएंगे।

हाथ से न जाने दें मौका

इतनी सारी मजेदार चीजों के साथ, द विंटर ड्रीम कार्निवल दिल्ली के इवेंट कैलेंडर में एक यादगार जगह बनाने जा रहा है। इसके टिकट अब उपलब्ध हैं और सीमित उपलब्धता के कारण, इस शानदार विंटर इवेंट का हिस्सा बनने के लिए जल्दी बुक करें। साथ ही ज्यादा जानकारी और टिकट खरीदने के लिए, विजिट करें BookMyShow, insider.in और Zomato Live।

दिल्ली में कब होंगे विधानसभा चुनाव? ECI ने अधिकारियों संग की बैठक

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग (ECI) हरकत में आ गया है। ECI ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची में संशोधन अभियान और चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मतदाता सूची में संशोधन मतदान केंद्रों की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा हुई।

नई दिल्ली। मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटने व फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनवाने के राजनीति दलों के आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव आयोग ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), निर्वाचन अधिकारियों व पुलिस (delhi police) के साथ एक बैठक की।

जिसमें मतदाता सूची में सुधार के लिए चल रहे विशेष सारांश संशोधन अभियान व आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के संशोधन अभियान में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करने व पूरी पारदर्शिता रखने का निर्देश दिया। साथ ही सीईओ व जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि मौके पर सत्यापन सत्यापन के बगैर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं काटा जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिया ये निर्देश

सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार बैठक में आयोग ने अपने निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। मतदाता सूची में संशोधन प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सीईओ और जिला निर्वाचन अधिकारियों को गौर करने भी निर्देश दिया है।

साथ ही राजनीतिक दलों की शिकायतों पर तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को सौंपने का निर्देश दिया है। ताकि आयोग उसकी समीक्षा कर सके। इसके अलावा आयोग ने निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों की आपत्तियों व शिकायतों का तुरंत व तथ्यात्मक रूप से निवारण होना चाहिए।

मतदाता सूची से नाम काटने से पहले ये काम करने के मिले निर्देश

मतदाता सूची में सुधार के लिए मिलने वाली शिकायतों और दावों को हर सप्ताह राजनीतिक दलों से साझा किया जाए और उसे सीईओ व जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए।

मतदाता सूची से किसी का नाम काटने से पहले बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मौके पर जानकर सत्यापन करना जरूरी है। इसके अलावा मतदाता को नोटिस भेजकर उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देना आवश्यक है। इसके बगैर किसी मतदाता का मतदाता सूची से नाम काटने की स्वीकृति नहीं है।

उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर भाजपा पर 22,649 वोट कटवाने का आरोप लगाया था। वहीं भाजपा आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटर बनवाने का आरोप लगा था। बहरहाल, विशेष सारांश संशोधन अभियान के तहत मतदाता सूची में सुधार और नए नाम शामिल करने के लिए सीईओ कार्यालय को एक माह करीब सवा दो लाख आवेदन मिले थे।

वैसे लोग अब भी मतदाता सूची में गलतियों सुधार के लिए आवेदन दे सकते हैं।24 दिसंबर तक मतदाता सूची में संशोधन की यह प्रक्रिया पूरी करनी है। इसके बाद छह जनवरी को फाइनल मतदाता सूची जारी होगी।

आप के 2100 रुपये देने के जवाब में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक, महिलाओं को लेकर कर दिया बड़ा एलान

सुषमा रानी

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर महिलाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने पिछले 11 वर्षों से महिलाओं की अनदेखी की है और अब चुनाव से पहले उन्हें 2100 रुपये देने का वादा कर रही है। यह महिलाओं के साथ धोखा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पार्टी की ओर से बड़ी घोषणा की।

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 वर्षों से महिलाओं की अनदेखी की है। अब आप संयोजक महिलाओं को 2100 रुपये देने का चुनावी वादा कर रहे हैं।

यह महिलाओं के साथ धोखा है। दो वर्ष पहले पंजाब विधानसभा चुनाव में भी वहां की महिलाओं से प्रति माह पैसे देने का वादा किया गया था, जिसे पूरा नहीं किया गया।

'फंड का प्रविधान होने के बाद भी महिलाओं को नहीं मिला लाभ'

उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार ने मार्च में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के अंतर्गत प्रति माह एक हजार रुपये देने की घोषणा की थी। फंड का प्रविधान होने के बाद भी आज तक महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिला।

दिल्ली में राशन और पेंशन बंद है। कांग्रेस सरकार द्वारा लागू लाडली योजना को समाप्त कर दिया गया। आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिका को पदमुक्त कर दिया गया।

आप सरकार सिर्फ केंद्र सरकार पर कर रही है दोषारोपण-कांग्रेस

अनुबंधित शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। अब उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए झूठे वादे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध व अत्याचार को रोकने की जगह आप सरकार सिर्फ केंद्र सरकार पर दोषारोपण करती है।

कांग्रेस की सरकार आने पर महिलाओं की सुरक्षा, विकास, उन्हें आत्म निर्भर बनाने और सरकारी पदों पर 50 प्रतिशत महिलाओं को नियुक्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा-केजरीवाल

वहीं पर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गुरुवार को दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी। जिसके तहत उन्होंने दिल्ली में सरकार बनने के बाद महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया। इसे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना नाम दिया गया है। बता दें, इससे ठीक पहले लोकसभा चुनाव से पहले भी केजरीवाल ने महिलाओं को हर माह 1000 रुपये देने की बात कही थी।

केजरीवाल ने इस संबंध में आगे की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना (Mukhyamantri Mahila Samman Yojana) के तहत रजिस्ट्रेशन शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। इसके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। इसके तहत महिलाओं को एक कार्ड दिया जाएगा, जिसे संभालकर रखना होगा।

दिल्ली महिला सम्मान योजना: क्या यह चुनावी रणनीति है या महिलाओं के लिए वास्तविक लाभ?

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज परिवहन विशेष

दिल्ली सरकार ने हाल ही में 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' की घोषणा की है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो 13 दिसंबर से शुरू होगा।

योजना के मुख्य बातें

– **लाभार्थी:** दिल्ली की स्थायी निवासी, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है।

– **आवश्यक दस्तावेज:** आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, बैंक विवरण, पते का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, और एक एफिडेविट।

– **रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया:** दिल्ली सरकार की वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके, आवश्यक दस्तावेजों के साथ नजदीकी केंद्र में जमा करना होगा।

चुनावी संदर्भ: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के निकट होने के कारण, इस योजना की घोषणा को कुछ राजनीतिक विश्लेषक चुनावी रणनीति के रूप में देख रहे हैं। हालांकि, योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, लेकिन चुनावी समय पर इसकी शुरुआत से कुछ सवाल उठ रहे हैं।

'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' दिल्ली की महिलाओं के लिए एक सकारात्मक कदम प्रतीत होती है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास है। हालांकि, योजना की सफलता और प्रभावशीलता चुनावी परिणामों और सरकार के कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।

मानवाधिकार की रक्षा के लिए चल रहे वैश्विक प्रयासों पर डाला गया प्रकाश

सुषमा रानी

नई दिल्ली: यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी फार ग्लोबल पीस (यूएनयूजीपी, यूएसए) और द अमेरिकन यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में एम्पावर सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का भव्य समारोह आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के कॉस्टीट्यूशन्स क्लब के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस समारोह में देश-विदेश से काफी संख्या में अतिथि एवं श्रोतागण मौजूद रहे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूएनयूजीपी और एयूजीपी यूएसए के अध्यक्ष और मुख्य रेक्टर प्रोफेसर डॉ. मधु कृष्णन तथा सेशेल्स के सांस्कृतिक एंबेसडर दीपक सिंह मौंजूद थे। इन अतिथियों का स्वागत डॉ. सोमशेखर के, दीपक दे और डॉ. घनश्याम के ने किया।

समारोह को संबोधित करते हुए प्रो. डॉ. मधु कृष्णन ने आज की दुनिया में मानवाधिकारों के महत्व के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने सभी देशों में शांति, समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए चल रहे वैश्विक प्रयासों पर प्रकाश डाला गया और इन मौलिक अधिकारों की रक्षा में वैश्विक शांति और सहयोग के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान, डॉ. कृष्णन ने वैश्विक शांति में उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी फार ग्लोबल पीस की ओर से मानद डॉक्टरेट की उपाधि और शांति दूत का प्रमाणपत्र भी प्रदान किया।

प्रो. डॉ. मधु कृष्णन को संबोधित करते हुए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से उनके आध्यात्मिक सलाहकार डॉ. मार्क बर्न्स द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में प्रो. डॉ मधु कृष्णन के पाँच महाद्वीपों में वैश्विक शांति को बढ़ावा देने में चार दशकों से अधिक समय तक उनके उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देते हुए उनके अथक कार्य और योगदान की प्रशंसा की गई, विशेष रूप से श्रीलंका में उनके हालिया शांति शिखर सम्मेलन की, जिसमें दुनिया भर से 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान कई प्रमुख व्यक्तियों को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई और उन्हें शांति दूत नामित किया गया, जिनमें डॉ. शोनिथ भट्ट, डॉ. स्नेहा धोबले, डॉ. विजय कुमार पंडित, डॉ. राजेंद्र बोरकर, डॉ. विजय नायडू, डॉ. जय प्रकाश, डॉ. दीपक कुमार और डॉ. रश्मि पांडे शामिल हैं।

कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन और फेलोशिप रात्रिभोज के साथ हुआ, जिसमें मानवाधिकारों और शांति पहलों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के आयोजन में एम्पावर सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की महासचिव सोनाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

'नहीं होगी जी हजूरी', टिकट कटने के बाद छलका आप विधायक का दर्द; कविता लिख जताई नाराजगी

सुषमा रानी

आप के टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। त्रिलोकपुरी विधायक रोहित मेहरौलिया टिकट कटने से नाराज हैं। उन्होंने पार्टी से अलग होने के संकेत दिए हैं। मेहरौलिया का कहना है कि उनकी टीम और समर्थक चाहते हैं कि वह चुनाव लड़ें। वह उस सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं जहां से अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं।

पूर्वी दिल्ली। आप के टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष की लकीर लंबी होती जा रही है। अब त्रिलोकपुरी विधायक रोहित मेहरौलिया टिकट कटने से नाराज हैं। न होगी जी हजूरी मुझसे...यह कविता एक्स पर पोस्ट कर कम शब्दों में नाराजगी की गहरी दास्तां उन्होंने बयां की है।

वह फिलहाल पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का संकेत देकर पार्टी से अलग होने का इशारा करते दिख रहे हैं। रोहित मेहरौलिया का कहना है कि उनकी टीम व समर्थक चाहते हैं कि वह चुनाव लड़ें। उन्होंने यहां तक कहा कि उनकी टीम चाहती है कि वह उस सीट से चुनाव लड़ें, जिससे आप के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरें।

2020 में मेहरौलिया को त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र से मिला था टिकट

रोहित मेहरौलिया आप के टिकट पर चुनाव लड़कर वर्ष 2017 में त्रिलोकपुरी वार्ड के पार्षद निर्वाचित हुए थे। उन्होंने उस वक्त कांग्रेस से मैदान में उतरीं अंजना पारचा को चुनाव हराया था। पार्षद के कार्यकाल के बीच ही वर्ष 2020 में मेहरौलिया को त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिल गया था। वह जीते और विधायक बन गए। इसी बीच अंजना न कांग्रेस छोड़ आप का दामन थाम लिया था। अब आप न मेहरौलिया की टिकट काटकर अंजना पारचा को इसी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है। इसे लेकर मेहरौलिया का कहना है कि टिकट बंटवारे में आप ने उनको नजरअंदाज किया है। वह सच्चे सिपाही के तौर पर पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। अन्ना आंदोलन के दिनों से लेकर पार्टी के बनने और उसके बाद हर कदम पर आप की नीतियों से काम किया। 15 साल पुरानी म्यूजिक टीचर की नौकरी छोड़ कर पार्टी को खड़ा करने में योगदान दिया। अब पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें मैंने वर्ष 2017 में निगम चुनाव में हराया था। वह कांग्रेस से करीब साढ़े तीन साल पहले आई हैं।

राहुल मित्रा ने इजरायल में भारतीय फिल्म एवं सांस्कृतिक साझेदारी को बढ़ाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया

Nurit Tinari

Rahul Mittra

सुषमा रानी

तेल अवीव: इजराइल और भारत के बीच सांस्कृतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए, इजराइल और भारतीय फिल्मोद्योग की प्रतिष्ठित हस्तियां आपसी तालमेल और सहयोग का पता लगाने का प्रयास कर रही हैं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत से एक शीर्ष फिल्म प्रतिनिधिमंडल, जिसमें जिसमें जाने-माने फिल्म निर्माता-अभिनेता और ब्रांडिंग विशेषज्ञ राहुल मित्रा और प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सीईओ नितिन तेज आहूजा शामिल थे, रविवार 1 दिसंबर को इजराइल के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित छह दिवसीय एक विशेष यात्रा पर तेल अवीव पहुंचा। भारतीय पक्ष इस यात्रा के दौरान इजराइली फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं, स्थानीय मीडिया, एआई विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के अलावा तेल अवीव, येरूसलम और हाइफा में फिल्मों की शूटिंग के लिए उपयुक्त स्थानों का दौरा भी करेगा। ब्यूरो फॉर कल्चरल डिप्लोमेसी इजराइल के प्रमुख नूरित तिनारी ने कहा कि यह इजराइल और भारत के लोगों के बीच आपसी संबंध को असैर प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। भारतीय सिनेमा इजराइल में काफी लोकप्रिय है, जबकि 'फौदा' जैसी इजराइली सीरीज ने भी भारत में एक समर्पित प्रशंसक प्राप्त किया है। जैसा कि हम इस मील के पत्थर का जश्न मना रहे हैं, हम आशा करते हैं कि दोनों प्राचीन सभ्यताएं और करीब आएंगी, जिससे हमारी मित्रता और मजबूत होगी।

दुनियाभर में कई भारतीय फिल्म प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व कर चुके राहुल मित्रा ने कहा, 'सिनेमा में लोगों को जोड़ने की अद्भुत क्षमता है और भारतीय फिल्मोद्योग दुनिया को लुभाने के लिए तैयार है, इसलिए हम लगातार नए स्थानों और ताजा कहानियों की तलाश में रहते हैं। इजरायल और भारत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समानताएं साझा करते हैं और हम सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाने और कला में सहयोग की तलाश के लिए इजरायल की यात्रा करने के लिए उत्साहित हैं।' इजरायल के प्रमुख फिल्म निर्माता एलन गुर आर्ये और एलाद पेलेग, मूवीलैंड सिनेमा चेन और बॉलीवुड टीवी चैनलों के मालिक शाई शिमशोन, लोकप्रिय टीवी और फिल्म अभिनेता और व्यापक रूप से देखी जाने वाली नेटफ्लिक्स श्रृंखला 'फौदा' के स्टार, त्सही हलेवी, भारतीय राजनयिक गार्सिया तेजेश्वर और सयाली, इजरायल में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के प्रमुख, मीका रोनेन, भारत ब्यूरो के पूर्व प्रमुख और हाइफा के मेयर योनाह याहव आदि तालमेल संबंधी अन्य उपायों की तलाश के क्रम में इजरायल में भारतीय प्रस्तुतियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पर आने वाले भारतीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान इजरायल के पारंपरिक व्यंजनों की पाक-कला संबंधी सैर, उसके बाद तेल अवीव के यूकेलिप्टस रेस्तरां में दोपहर का भोजन, बाइबिल के व्यंजनों से प्रेरित स्थानीय उत्पादों की विशेषता, याद वाशेम, होलोकॉस्ट संग्रहालय की यात्रा और येरुशलम के पुराने शहर का निर्देशित दौरा कुछ मुख्य आकर्षण होंगे।

सिटी बस टर्मिनल में खुलेगा अस्पताल, संचालन के लिए 4 कंपनियां आईं सामने

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा सिटी बस टर्मिनल की खाली पड़ी इमारत को किराए पर देने की तैयारी चल रही है। प्री-बिड बैठक में अस्पताल संचालन के लिए चार कंपनियां आई हैं। 17 फरवरी को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) खोली जाएगी और चयनित कंपनी को इमारत का स्ट्रक्चर बदले बिना ही अपना प्लान बनाना होगा। सिटी बस टर्मिनल 30 हजार 643 वर्ग मीटर एरिया में बना हुआ है।

नोएडा। सेक्टर-82 स्थित सिटी बस टर्मिनल की खाली पड़ी इमारत को किराये पर देने की तैयारी प्राधिकरण में चल रही है। बस टर्मिनल में अस्पताल के संचालन को प्री बिड बैठक में चार कंपनियां आयी है।

अब यह तो लगभग तय हो गया है कि इस सिटी बस टर्मिनल की इमारत में अस्पताल का ही संचालन ही किया जाएगा। 17 फरवरी को रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) खोली जाएगी। इसमें जो भी कंपनियां आएंगी, अपना प्रपोजल प्राधिकरण को देंगी। उसमें से किसी एक कंपनी को चयनित किया जाएगा।

बदला जाएगा बिल्डिंग बायलाज

नोएडा ट्रैफिक सेल महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि टर्मिनल इमारत का बायलाज ट्रांसपोर्ट यूज के लिए है। ऐसे में प्रपोजल पसंद आने और अप्रूव होने के बाद ही इसका बिल्डिंग बायलाज बदला जाएगा। बायलाज बदलने की प्रक्रिया बोर्ड से की जाएगी।

साथ चयनित होने वाली कंपनी टर्मिनल की इमारत के स्ट्रक्चर के साथ कोई बदलाव नहीं कर सकती है। उसे इसी इमारत स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना प्लान करना होगा।

ऐसे में ईओआई के ब्रोशर में आठ मंजिला इस टर्मिनल के फ्लोर वाइज जानकारी दी गई है। अभी इस इमारत में परिवहन निगम के अलावा एक साइबर क्राइम पुलिस का दफ्तर खुला हुआ है। अब इसको किराए पर दिया जाएगा।

दो हिस्सों में बंटी है सिटी बस टर्मिनल की इमारत

सिटी बस टर्मिनल 30 हजार 643 वर्ग मीटर एरिया में बना हुआ है, जिसमें से 13 हजार 532 वर्ग मीटर एरिया बिल्टअप है यानी इतने हिस्से में निर्माण हो रखा है। सिटी बस टर्मिनल इमारत दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक हिस्से में बेसमेंट के अलावा तीन दो हैं जबकि दूसरे हिस्से में तीसरे से आठ तल तक का हिस्सा बना हुआ है।

बेसमेंट में 522 कार खड़ी करने की पार्किंग है। भूतल पर बस संचालन का एरिया संचालित हो रहा है जिसमें 40 बस पार्किंग के अलावा 100 कार व टैक्सी पार्किंग की सुविधा है। इनके अलावा स्वागत कक्ष, बुकिंग सेंटर, आफिस, प्रतीक्षालय, कॉरिडोर व फूड कोर्ट के लिए स्थान आरक्षित हैं। प्रथम तल पर दुकान, आफिस, फूड कोर्ट और लाइब्रेरी कमरा बना हुआ है। द्वितीय तल पर यात्री निवास, साइबर कैफे, फूड कोर्ट, काउंटर और प्रतीक्षालय एरिया बना हुआ है।

जनवरी 2015 में शुरू हुआ सिटी बस टर्मिनल का काम

बता दें कि इमारत तैयार होने के बाद प्राधिकरण ने इसे हैंडओवर करने के लिए परिवहन निगम से संपर्क किया था, लेकिन निगम ने पूरी इमारत टेकओवर करने से ही इंकार कर दिया था। खानापूर्ति के लिए दादरी और बुलंदशहर के लिए 4 बसें चलवानी शुरू की।

दावा किया था इन बसों की संख्या बढ़ाकर 50 की जाएगी, लेकिन तीन साल बाद भी 4 बसें ही टर्मिनल से चल रही हैं। सिटी बस टर्मिनल का काम जनवरी 2015 में शुरू हुआ था। इसकी पहली डेडलाइन जुलाई 2016 थी लेकिन जमीन विवाद और मामला न्यायालय में चले जाने के कारण काम रूक गया। इसके बाद इसका काम सितंबर 2022 में जाकर पूरा हुआ। ये 157 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई थी।

'पहले आओ अधिक लाभ पाओ' यूपी के इस जिले में बिजली बकायेदारों के लिए बड़ी राहत, तीन लाख लोगों का ब्याज होगा माफ

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत जिले के तीन लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं का 135 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा। सबसे ज्यादा फायदा जोन दो (लोनी मुरादनगर और मोदीनगर) के उपभोक्ताओं को मिलेगा। यहां के 1.75 लाख उपभोक्ताओं का 127 .22 करोड़ रुपये का ब्याज माफ होगा।

साहिबाबाद। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में जिले के तीन लाख उपभोक्ताओं का 135 करोड़ ब्याज की राशि माफ होगी। सबसे अधिक जोन दो (लोनी, मुरादनगर व मोदीनगर) के उपभोक्ताओं का योजना का लाभ मिलेगा।

यहां के 1.75 लाख उपभोक्ताओं का 127.22 करोड़ माफ होगा। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 30 व अधिकतम सौ प्रतिशत तक ब्याज माफ किया जाएगा। यानी चरण बदलने के साथ ही योजना में मिलने वाला लाभ कम होता जाएगा।

जिले में विद्युत निगम के जोन-एक (शहर), जोन-दो (लोनी, मुरादनगर व मोदीनगर) व जोन तीन (ट्रांस हिंडन) में करीब 11 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से छोटे-बड़े 306457 विद्युत निगम के बकायेदार हैं। इन पर निगम का करीब 400 करोड़ बकाया है।

बकायेदार बिल का बकाया जमा कर सकें इसके लिए हर वर्ष ओटीएस योजना लाई जाती है। इस बार भी 15 दिसंबर से बकायेदारों को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जो 31 जनवरी 2025 तक मिलेगा।

इसमें उपभोक्ताओं को अलग-अलग चरण व श्रेणी के कनेक्शन के अनुसार योजना का लाभ दिया जाएगा। जो पहले चरण में पंजीकरण कर बकाया जमा करेगा उसे अधिक व बाद में आएगा उसे कम लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए कुल बकाये का न्यूनतम 30 प्रतिशत जमा करना होगा।

मुरादनगर, मोदीनगर व लोनी में सबसे अधिक बकायेदार व बकाया

मोदीनगर, मुरादनगर व लोनी विद्युत निगम के जोन-दो के अंतर्गत आते हैं। यहां विद्युत निगम के सबसे अधिक बकाएदार व बकाया हैं। यहां एक लाख, 75 हजार 592 उपभोक्ताओं पर 127.94 करोड़ केवल ब्याज का बकाया है। साथ ही बिल का कुल बकाया व ब्याज को मिलाकर कुल 334 करोड़ के करीब है।

कौन सा चरण कब तक चलेगा

पहला चरण 15 से 31 दिसंबर
दूसरा चरण एक से 15 जनवरी
तीसरा चरण 16 से 31 जनवरी

ओटीएस योजना में जोनवार बकायेदार व ब्याज की राशि

जोन	उपभोक्ता	कुल ब्याज
जोन-एक	51	
जोन-दो	1,75 592	127.94
जोन-तीन	79 722	2.94

(नोट : राशि करोड़ में है)

किस श्रेणी में कुल कितने बकायेदार

कनेक्शन जोन-एक जोन-दो जोन-तीन

घरेलू उपभोक्ता (एलएमवी-1) 44,097 1,58,997 66,536
वाणिज्यिक (एलएमवी-2) 6,639 15,288 12,495
निजी संस्थान (एलएमवी-4) 72 122 84
लघु-मध्यम उद्योग (एलएमवी-6) 335 1185 607

योजना का लाभ 15 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। पहले आओ, अधिक लाभ पाओ के आधार पर योजना में लाभ दिया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को विभिन्न माध्यम से जागरूक भी किया जा रहा है।

नरेश भारती, मुख्य अभियंता, विद्युत निगम जोन-दो।

बदमाशों के लिए काल साबित हो रही यूपी पुलिस, एक साल में गैंगस्टरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

यूपी में गुंडों और बदमाशों की अब खैर नहीं। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने एक साल में अभी तक सात सौ गैंगस्टरों पर कार्रवाई की है। जबकि गैंगस्टर के 50 मामलों में कुल 02 अरब 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अपने अधीन की। वहीं पर सैंकड़ों अपराधियों पर गुंडा एक्ट लगाया गया। एक क्लिक में पढ़ें पूरी खबर।

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस (Noida Police) ने इस साल जरायम (अपराध की दुनिया) की दुनिया में जड़ें जमा चुके बड़े-बड़े अपराधियों पर कार्रवाई की है। एक जनवरी से लेकर अब तक सात सौ गैंगस्टरों पर कराई की है। गैंगस्टर के 50 मामलों में कुल 02 अरब 10 करोड़ 79 लाख 21 हजार 475 रुपये की संपत्ति जब्त की है।

612 अपराधियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। 198 इनामी बदमाशों में से 156 को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा है। 162 अपराधी जिला बदर किए गए हैं। जिला बदर होने के बावजूद जिले में मिलने पर 40 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं।

एक लाख का इनामी भी गिरफ्तार : पुलिस ने बताया कि जिले भर में विभिन्न अपराधों में संलिप्त 198 अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया। उनमें से 156 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। उनमें एक लाख का एक, 25 हजार के 66, 20 हजार के चार, 15 हजार के 20, 10 हजार के 52, पांच हजार के 13 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए।

इनामी अपराधियों पर जोनवार कार्रवाई

62 इनामी बदमाश घोषित किए गए। 47 गिरफ्तार हुए। उनमें 25 हजार के 24, 20 हजार के चार, 15 हजार के 12, 10 हजार के सात इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए।

नोएडा के करीब 50,000 फ्लैट खरीददारों के लिए गुड न्यूज, घर मिलने का रास्ता हुआ साफ

परिवहन विशेष न्यूज

राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सुपरटेक समूह की उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा कर्नाटक में अटकी 16 परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) को सौंप दी है। इस फैसले से 49748 फ्लैट खरीदारों (Noida Real Estate News) को राहत मिलेगी। एनबीसीसी को यह काम 12 से 36 महीने में पूरा करना होगा। पढ़ें खबर ते संबंध में पूरा अपडेट।

नोएडा। राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सुपरटेक समूह की उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक में अटकी 16 परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) को सौंप दी है।

यह निर्माण कार्य एनबीसीसी को 12 से 36 माह में पूरा करना होगा, जिस पर 9945 करोड़ रुपये खर्च होंगे। परियोजनाओं के पूरा होने से कुल 49,748 फ्लैट खरीददारों को उनका आशियाना मिलेगा।

घर निवेशकों और खरीदारों का बढ़ेगा भरोसा

बता दें कि एनसीएलएटी के इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्अर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। इससे घर निवेशकों और खरीददारों का भरोसा बढ़ेगा। एनबीसीसी के आने से अब इको विलेज-3, स्पोर्ट्स विलेज, इको सिटी।

नाथ आई, अपकंट्री, इको विलेज-1, मेरठ स्पोर्ट्स सिटी, ग्रीन विलेज, हिलटाउन, अरावली, रिवर फ्रेंष्ट, इकोविलेज, केपटाउन प्रोजेक्ट के निर्माण को गति मिलेगी। घर खरीददारों के हितों की रक्षा भी होगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के मानदंडों के अनुरूप ही यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय की खास बात यह है कि इसके लिए फ्लैट खरीददारों को सिर्फ वहीं पैसा देना है जो बिल्डर पर उसका पेंडिंग है। हालांकि इन परियोजनाओं के बनने वाले फ्लैट का अधिकांश पैसा खरीददार बिल्डर को दे चुके हैं।

प्रोजेक्ट के तहत कुल 49,748 फ्लैट का होना है निर्माण

इन परियोजनाओं में से ज्यादातर में लंबे समय से काम अटका हुआ है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब 9945 करोड़ रुपये का खर्च होंगे। हालांकि सुपरटेक के कुल 17 प्रोजेक्ट है, जिसमें एक परियोजना दिवालियापन की प्रक्रिया में हैं। इन प्रोजेक्ट के तहत कुल 49,748 फ्लैट का निर्माण होना है।

निर्माण कार्य मई 2025 में शुरू किया जा सकता है। इससे पहले कंपनी को एक एस्क्रो अकाउंट खोलना होगा। यह अकाउंट नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी और इनसाल्वेंसी रीजोल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) दोनों की निगाह में रहेगा।

इसी खाते से पैसा निर्माण में खर्च किया जाएगा। इस फैसले के बाद घर खरीदार, एक-दूसरे को बधाई दे रहे हैं। एनसीएलएटी ने सुपरटेक की इन अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी को व्यापक योजना तैयार करने का अधिकार दिया है।

एनबीसीसी का कहना है कि परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत लगभग 9,445 करोड़ रुपये है, जिसमें 3 प्रतिशत आकस्मिकता शामिल है। परामर्श शुल्क 8 प्रतिशत तय किया गया है, जिसमें एक प्रतिशत विपणन शुल्क शामिल है। एनबीसीसी पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आम्रपाली समूह की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा कर रही है।

विकास लक्ष्यों को पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ जोड़ना अत्यन्त आवश्यक

हम पाते हैं कि सामाजिक लक्ष्यों का पीछा करना, आम तौर पर, उच्च पर्यावरणीय प्रभावों से जुड़ा होता है। हालाँकि, देशों के बीच बातचीत बहुत भिन्न होती है और विशिष्ट लक्ष्यों पर निर्भर करती है। दोनों ही बातचीत में, कार्बन भूमि और पानी की तुलना में छोटे बदलावों का अनुभव करता है। हालाँकि उच्च और निम्न आय समूहों द्वारा प्रयासों की आवश्यकता है, लेकिन अमीरों के पास मानवता के पदचिह्नों को कम करने का अधिक लाभ है। सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों के महत्त्व को देखते हुए, यह महत्त्वपूर्ण है कि एसडीजी के बीच मात्रात्मक बातचीत को अच्छी तरह से समझा जाए ताकि जहाँ ज़रूरत हो, एकीकृत नीतियाँ विकसित की जा सकें।

-डॉ.सत्यवान सौरभ

जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत का सह-लाभ दृष्टिकोण विकास लक्ष्यों को पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ संरेखित करने का प्रयास करता है, जलवायु चुनौतियों का समाधान करते हुए सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को एकीकृत करके, इस रणनीति का उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना और लचीलापन बढ़ाना है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जैसी पहल इन प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम पाते हैं कि सामाजिक लक्ष्यों का पीछा करना, आम तौर पर, उच्च पर्यावरणीय प्रभावों से जुड़ा होता है। हालाँकि, देशों के बीच बातचीत बहुत भिन्न होती है और विशिष्ट लक्ष्यों पर निर्भर करती है। दोनों ही बातचीत में, कार्बन भूमि और पानी की तुलना में छोटे बदलावों का अनुभव करता है। हालाँकि उच्च और निम्न आय समूहों द्वारा प्रयासों की आवश्यकता है, लेकिन अमीरों के पास मानवता के पदचिह्नों को कम करने का अधिक लाभ है। सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों के महत्त्व को देखते हुए, यह महत्त्वपूर्ण है कि एसडीजी के बीच मात्रात्मक बातचीत को अच्छी तरह से समझा जाए ताकि जहाँ ज़रूरत हो, एकीकृत नीतियाँ विकसित की जा सकें।

भारत का सह-लाभ दृष्टिकोण, जो कई मोर्चों पर एक साथ प्रगति के लिए विकास लक्ष्यों को पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ जोड़ता है: भारत का सह-लाभ दृष्टिकोण सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए जलवायु परिवर्तन को सम्बोधित करता है, जलवायु क्रियाओं को ग़रीबी में कमी और ऊर्जा पहुँच जैसे लक्ष्यों के साथ जोड़ता है। पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना न केवल अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है बल्कि कम आय वाले परिवारों को सस्ती बिजली भी प्रदान करती है। जलवायु क्रियाओं को विकास लक्ष्यों के साथ जोड़कर, सह-लाभ दृष्टिकोण पर्यावरणीय पहलों में सार्वजनिक समर्थन और भागीदारी को बढ़ाता है। पीएम ई-ड्राइव इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे शहरी वायु प्रदूषण को सम्बोधित करते हुए उन्हें सुलभ बनाया जा सके और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके। जलवायु और विकास लक्ष्यों को एकीकृत करके, संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग किया जाता है, जिससे नीति कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण लागत बचत होती है।

प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना उद्योगों को ऊर्जा दक्षता में सुधार करने, लागत कम करने और उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। यह दृष्टिकोण कृषि, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में लचीलापन बढ़ाने पर ज़ोर देता है, जो कमजोर आबादी के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएँ क्षेत्र-विशिष्ट कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों के लिए लक्षित अनुकूलन रणनीतियों को सुनिश्चित करती हैं। सह-लाभ दृष्टिकोण जलवायु और विकासात्मक चुनौतियों दोनों को सम्बोधित करने वाली नवीन तकनीकों के विकास और तैनाती को प्रोत्साहित करता है। सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणालियों का विकास टिकाऊ कृषि का समर्थन करता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है।

इन प्राथमिकताओं को संतुलित करने में इस रणनीति की प्रभावशीलता उत्सर्जन में कमी और आर्थिक विकास के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर है। भारत ने आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए अपनी उत्सर्जन तीव्रता को कम करने में प्रगति की है, जो सह-लाभ दृष्टिकोण की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन को लगातार कम किया है। यह रणनीति नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव को गति देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुँच की खाई को सफलतापूर्वक पाटती है। छतों पर सौर ऊर्जा पहलों ने दूरदराज के गांवों में बिजली पहुँचाई है, जिससे डीजल जनरेटर पर निर्भरता कम हुई है। भारत की रणनीति जलवायु क्रियाओं को निधि देने के लिए घरेलू पहलों पर केंद्रित है। इस आत्मनिर्भरता ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। भारतीय कार्बन बाज़ार उद्योगों में उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू संसाधनों को जुटाता है। जबकि यह दृष्टिकोण संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देता है, लेकिन तेज़ आर्थिक विकास की आवश्यकता कभी-कभी पर्यावरण संरक्षण में समझौता करने की ओर ले जाती है। तत्काल ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का विस्तार शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियाँ पेश करता है। राज्य कार्य योजनाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत जलवायु कार्यवाही यह सुनिश्चित करती है कि क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों को पर्याप्त रूप से सम्बोधित किया जाए। अहमदाबाद जैसे शहरों में हीट एक्शन प्लान ने अत्यधिक गर्मी के प्रभावों को कम करने में मदद की है, जिससे कमज़ोर आबादी की रक्षा हुई है। जबकि सह-लाभ दृष्टिकोण पायलट कार्यक्रमों में प्रभावी रहा है, देश भर में इन पहलों को आगे बढ़ाना एक चुनौती बनी हुई है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास अभी भी पिछड़ा हुआ है।

भारत का सह-लाभ दृष्टिकोण जलवायु कार्यवाही को विकास के साथ प्रभावी ढंग से संतुलित करता है। यह स्थिरता और लचीलेपन को बढ़ावा देता है। अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और हरित बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश इस रणनीति को मज़बूत करेगा। यह स्थानीयकृत, प्रभावशाली समाधानों के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के सिद्धांत को दर्शाता है, जो विकास और पर्यावरणीय लक्ष्य दोनों में सार्थक प्रगति को आगे बढ़ाता है।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर

मुंबई में 2027 तक 8,000 ई-बसें चलाने की योजना

परिवहन विशेष न्यूज

मुंबई की सार्वजनिक परिवहन कंपनी बेस्ट ने अपने 2025-26 के बजट प्रस्ताव के अनुसार , 2027 तक अपने बेड़े का महत्वपूर्ण विस्तार करने और पूर्ण विद्युतीकरण हासिल करने की योजना बनाई है। सार्वजनिक परिवहन कंपनी का लक्ष्य अपने बेड़े को मौजूदा 711 इलेक्ट्रिक बसों से बढ़ाकर कुल 8,000 करना है, इस प्रक्रिया में पुराने, गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार , इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेस्ट का इरादा सालाना 2,650 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का है।

विस्तार के हिस्से के रूप में, प्रस्ताव में 1,000 इलेक्ट्रिक एसी डबल-डेकर बसों का अधिग्रहण शामिल है, जिससे निकट भविष्य में इन प्रतिष्ठित बसों की संख्या 1,200 हो जाएगी। वर्तमान में, बेड़े में 2,911 बसें हैं, जिनमें से 711 इलेक्ट्रिक हैं, जिनमें 50 एसी डबल-डेकर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 150 और एसी डबल-डेकर खरीदने का काम चल रहा है। बेस्ट की योजना अगले चार महीनों में 510 पुरानी बसों को हटाने की भी है।

हालांकि, जैसा कि व्यापार एजेंसी इलेक्ट्रिव डॉट कॉम ने बताया है , यह स्पष्ट नहीं है कि रक्या ये इलेक्ट्रिक बसें मई 2022 में बेस्ट द्वारा ऑर्डर की गई 2,100 इकाइयों और/या फरवरी 2024 में कंपनी द्वारा ऑर्डर की गई 2,400 इकाइयों के अतिरिक्त हैं या उनमें शामिल हैं , दोनों ही ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक से हैंर। किसकी डिलीवरी में देरी हो रही है'

2,100 इलेक्ट्रिक बसों के लिए पिछले समझौते के बावजूद, अब तक केवल 275 ही वितरित किए गए हैं, जो लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती को उजागर करता है। हालांकि, बेस्ट के महाप्रबंधक अनिल डिग्गीकर ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा बजट को मंजूरी दिए जाने के बाद 1,000 नई डबल-डेकर बसों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डिग्गीकर के अनुसार, डबल-डेकर बसों की संख्या में वृद्धि से बस स्टॉप पर भीड़भाड़ कम करने, यातायात को आसान बनाने और क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, खासकर दक्षिण मुंबई और उपनगरीय क्षेत्रों के मार्गों पर, जहां ऐसी बसों की सबसे अधिक आवश्यकता है।

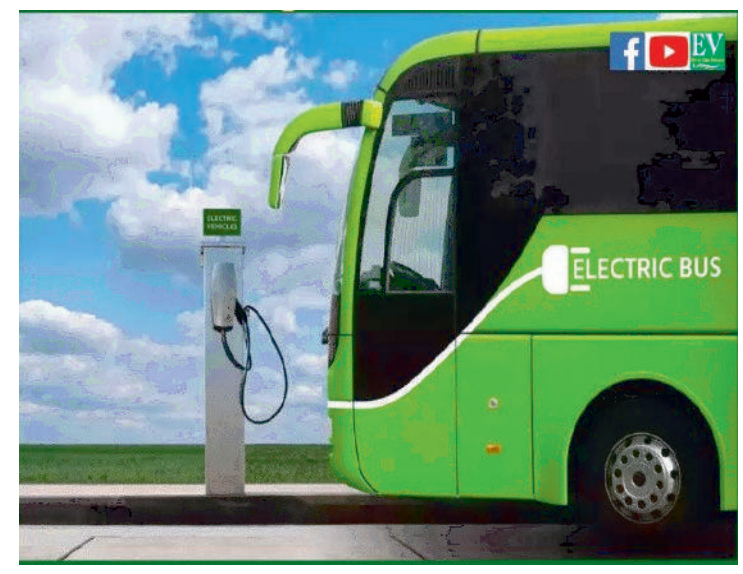

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ने वाणिज्यिक ईवी के लिए बैटरी-एज़-ए-सर्विस लॉन्च करने के लिए विद्युत के साथ की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड ने विद्युत के साथ मिलकर अपने 4 व्हीलर और 3 व्हीलर वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी-एज़-ए-सर्विस पहल की घोषणा की है।

बैटरी-एज़-ए-सर्विस कार्यक्रम 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होने वाले भुगतान-योग्य किराये का विकल्प प्रदान करता है, जो इन इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की प्रारंभिक लागत को 40% तक कम करने में मदद करता है।

बेंगलुरु स्थित फुल-स्टैक ईवी स्टार्टअप विद्युत ग्राहकों को बैटरी खरीदने के बजाय उसे किराए पर लेने का विकल्प देगा। इससे ग्राहकों को 4 व्हीलर महिंद्रा जिओ, ज़ोर ग्रैंड और 3 व्हीलर ट्रियो प्लस जैसी ईवी खरीदने की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलेगी।

बैटरी-एज़-ए-सर्विस मॉडल के अंतर्गत, वाहन मालिकों को किराये के कार्यक्रम को जारी रखने या वित्तपोषण अवधि के अंत में बैटरी खरीदने की सुविधा मिलती है।

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड की प्रबंध निदेशक और सीईओ सुमन मिश्रा ने कहा, रबैटरी-एज़-ए-सर्विस विकल्प के माध्यम से, हमारा लक्ष्य प्रारंभिक लागत को कम करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अधिक सुलभ बनाना है, जिससे वाणिज्यिक क्षेत्र में ईवी को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा मिले।"

विद्युत के सह-संस्थापक, ज़ीतिज कोठी ने इस बात पर जोर दिया, "हमारा दृष्टिकोण बैटरी को एक सेवा के रूप में मानने पर केंद्रित है, जिससे ग्राहकों को केवल बैटरी के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके और साथ ही ईवी स्वामित्व का वित्तीय बोझ कम हो सके।"

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड भारत की अग्रणी इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी है, जो ट्रिओ, ज़ोर ग्रैंड और ई-अल्फा वाहनों सहित इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, सीएनजी और डीजल लास्ट-माइल मोबिलिटी समाधानों की विस्तृत श्रृंखला पेश करती है।

बैटरी-एज़-ए-सर्विस एक ऐसा व्यवसाय मॉडल है जो इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को बैटरी को सीधे खरीदने के बजाय वाहन से अलग से किराए पर लेने की अनुमति देता है। इस दृष्टिकोण ने शुरुआती लागत को कम करने, सामर्थ्य को बढ़ाने और व्यापक ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में गति प्राप्त की है।

बैटरी-एज़-ए-सर्विस मॉडल में बैटरी के स्वामित्व को वाहन से अलग रखा जाता है, जिससे ग्राहक बैटरी के उपयोग के लिए किलोमीटर की संख्या के आधार पर भुगतान कर सकते हैं। इससे ईवी खरीदने के लिए आवश्यक प्रारंभिक निवेश कम हो जाता है, जिससे यह वाणिज्यिक और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाता है। किराये की लागत आमतौर पर भुगतान-प्रति-उपयोग शुल्क के रूप में संरचित होती है, जो अक्सर यात्रा की गई दूरी पर आधारित होती है, जिससे अक्सर ईवी खरीदने के साथ आने वाले वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिलती है।

बैटरी-एज़-ए-सर्विस मॉडल वाणिज्यिक बेड़े के लिए परिचालन दक्षता में सुधार कर सकते हैं, खासकर लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी जैसे क्षेत्रों में, जहां वाहनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। बैटरी-एज़-ए-सर्विस की पेशकश करने वाली कंपनियाँ बैटरी के रखरखाव, प्रतिस्थापन और रीसाइक्लिंग को भी संभालती हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि बैटरियों का उचित प्रबंधन किया जाए और आवश्यकतानुसार उन्हें अपग्रेड किया जाए।

इस मॉडल में बैटरी की लागत, जीवनचक्र और प्रदर्शन से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की क्षमता है, जिससे ग्राहकों को अधिक लचीलापन और कम वित्तीय जोखिम मिलेगा। यह संसाधन उपयोग को अनुकूलित करते हुए और बैटरी उत्पादन और निपटान से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए ईवी अपनाने को प्रोत्साहित करके व्यापक स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है। (एएफपी)

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने शुरू की महिंद्रा के साथ मिलकर ऑल-इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों को प्रीमियम, पूर्णतः इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा प्रदान करने के लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स मोबिलिटी के साथ साझेदारी की है।

यह सेवा 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा चलाएगी, जिससे यात्रियों को आरामदायक, पर्यावरण-अनुकूल यात्रा मिलेगी। यात्री आगमन और प्रस्थान के समय परेशानी मुक्त पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ का आनंद ले सकते हैं, जिससे हवाई अड्डे तक पहुंचना और वापस आना आसान हो जाता है।

24/7 उपलब्ध यह सहयोग एक सहज और टिकाऊ यात्रा अनुभव की गारंटी देता है। यात्री एक समर्पित मोबाइल ऐप, वेबसाइट, कॉल सेंटर, एयरलाइन भागीदारी और हवाई अड्डे के कियोस्क के माध्यम से सवारी बुक कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बुकिंग सभी के लिए सरल और सुलभ है।

एनआईए के सीईओ क्रिस्टोफ श्नेलमैन ने नई सेवा के बारे में बताते हुए कहा, रहम महिंद्रा लॉजिस्टिक्स मोबिलिटी के साथ साझेदारी करके एक प्रीमियम, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा की पेशकश करने के लिए उत्साहित हैं, जो हवाई अड्डे से सीधे आपके गंतव्य तक एक निर्बाध और पर्यावरण के अनुकूल सवारी प्रदान करेगी।र

यह सेवा सुरक्षा और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें ड्राइवरों को हवाई अड्डे के प्रोटोकॉल और ग्राहक सेवा पर व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यात्रियों की मांग और उड़ान के शेड्यूल के आधार पर वास्तविक समय में समायोजन किया जाएगा, जिससे प्रतीक्षा समय कम होगा और सेवा की उपलब्धता बढ़ेगी। सेवा में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए एक फीडबैक सिस्टम लागू किया जाएगा।

मुरुगप्पा समूह की टिवोल्ट और टाटा पावर का ईवी चार्जिंग नेटवर्क विस्तार के लिए की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

मुरुगप्पा समूह द्वारा संचालित टीसीआई क्लीन मोबिलिटी की सहायक कंपनी टिवोल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने बुधवार, 11 दिसम्बर को कहा कि उसने अपने इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के लिए चार्जिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए ईवी चार्जिंग समाधान प्रदाता टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि सहयोग के तहत, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी देश भर में रणनीतिक स्थानों पर टिवोल्ट डीलरशिप, ग्राहक स्थानों और उच्च यातायात वाले सार्वजनिक स्थानों पर एक विशाल ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना और प्रबंधन में अपने व्यापक अनुभव को लाएगी।

टिवोल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सीईओ साजू नायर ने कहा, रयह रणनीतिक साझेदारी ईवी अपनाने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण सहायक होगी और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी लाएगी। यह समझौता ज्ञापन ई-ट्रकों के लिए ईवी इकोसिस्टम को मजबूत, सुलभ चार्जिंग समाधानों के साथ सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।र

इसके अलावा टीपीआरईएल टिवोल्ट डीलरशिप और ग्राहक स्थानों को बिजली प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा प्रणालियों के एकीकरण की संभावना भी तलाशेगा।

टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के सीईओ और एमडी दीपेश नंदा ने कहा, रएक मजबूत और अच्छी तरह से एकीकृत ईवी इकोसिस्टम वाणिज्यिक ईवी को अपनाने में तेजी लाएगा, जिससे भारत के ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा और अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा।"

बयान के अनुसार छोटे इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के लिए आसान चार्जिंग समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए टीपीआरईएल ने पहले मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे और कोच्चि सहित 100 से अधिक शहरों में ग्राहकों को 200 से अधिक अनुकूलित ईवी चार्जिंग स्टेशन प्रदान करने के लिए अन्य ओईएम (मूल उपकरण निर्माताओं) के साथ साझेदारी की है।

टीपीआरईएल ने ईज़ी चार्ज ब्रांड नाम के तहत अपने नेटवर्क का विस्तार 1,00,000 से अधिक घरेलू चार्जर, 6,500 से अधिक सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक और फ्लीट चार्जिंग प्वाइंट्स के साथ-साथ 530 शहरों और कस्बों में 1,100 से अधिक बस चार्जिंग स्टेशनों तक कर दिया है।

भारतीय प्रतिभा तंजानिया की इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति को बढ़ा रही है आगे

परिवहन विशेष न्यूज

तंजानिया का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 2031 तक लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की राह पर है, जो 31% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है, जिसमें भारत ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग इंजीनियरिंग, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी भूमिकाओं के लिए एक प्रमुख प्रतिभा प्रदाता के रूप में उभर रहा है।

तंजानिया के ईवी निवेश इंजीनियरिंग, अनुसंधान, विनिर्माण और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहे हैं। उल्लेखनीय रूप से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध भारतीय पेशेवरों से बैटरी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से लेकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परियोजना प्रबंधकों तक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने की उम्मीद है।

बैटरी डिजाइन, पावरट्रेन इंजीनियरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे प्रमुख कौशल की बहुत मांग है। ईवी सेक्टर के विकास ने दोनों देशों में एक महत्वपूर्ण कौशल अंतर को उजागर किया है, जिसमें भारत को ईवी से संबंधित विशेषज्ञता में 40-45% की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

प्लग एन राइड के सीईओ ज़फ़र इकबाल का अनुमान है कि भारत को ईवी अपनाने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक 2,00,000 कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी। इस अंतर को पाटने के लिए इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को अपडेट करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

भारतीय और तंजानिया कंपनियों के बीच साझेदारी इस कार्यबल परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है। हाल के सहयोगों में तंजानिया में प्लग एन राइड का ईवी मोटरसाइकिल असेंबलिंग प्लांट में ईवी के निर्माण के लिए उद्यम शामिल हैं। ये पहल न केवल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ाती हैं बल्कि बैटरी रीसाइक्लिंग, स्मार्ट ग्रिड एकीकरण और संधारणीय गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में कैरियर के अवसर भी प्रदान करती हैं।

तंजानिया में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना स्थिरता और नवाचार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है। भारतीय पेशेवर सिर्फ पदों को ही नहीं भर रहे हैं, बल्कि वे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य को आकार दे रहे हैं। यह सहयोग सुनिश्चित करता है कि दोनों देश साझा विशेषज्ञता, उच्च वेतन और अधिक टिकाऊ भविष्य से लाभान्वित हों।

तंजानिया खुद को स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य की गतिशीलता में अग्रणी के रूप में स्थापित कर रहा है, इसलिए इसके कार्यबल की गतिशीलता विकसित हो रही है। भारतीय पेशेवर, जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं, तंजानिया की ईवी महत्वाकांक्षाओं के लिए तेजी से केंद्रीय बन रहे हैं। 2029 तक ईवी बिक्री में 2.26 बिलियन अमरीकी डॉलर के अनुमानित बाजार वॉल्यूम के साथ, यह वृद्धि दीर्घकालिक कैरियर के अवसर पैदा कर रही है जो प्रतिस्पर्धी वेतन, कौशल विकास और सीमा पार गतिशीलता प्रदान करते हैं।

किआ कार्निवाल की भारत में बड़ी मांग, 2 महीने में डिलीवर हुई 400 यूनिट्स, अब हुआ छह महीने का वेटिंग पीरियड

भारतीय बाजार में October 2024 में प्रीमियम MPV Kia Carnival की नई जेनरेशन को लॉन्च किया था। लॉन्च के दो महीने में ही इसकी 400 से ज्यादा डिलीवरी (Kia Carnival demand in India) की जा चुकी हैं। कंपनी की आरे से बताया गया है कि इस एमपीवी के लिए कुल कितनी बुकिंग मिल चुकी हैं और इसको घर लाने के लिए कितना इंतजार करना होगा।

नईदिल्ली। प्रीमियम MPV सेगमेंट में Kia की ओर से October 2024 में ही नई जेनरेशन वाली Kia Carnival 2024 को लॉन्च किया गया है। लॉन्च के साथ ही देश में इस गाड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। दो महीने में ही इसकी 400 से ज्यादा यूनिट्स की डिलीवरी की जा चुकी है और अब इसके लिए कितनी बुकिंग कंपनी को मिल चुकी हैं। आज बुक करवाने पर कितने समय में इसे घर ले जाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Kia Carnival MPV की बाजार में बड़ी मांग: साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Kia की ओर से अक्टूबर 2024 में ही कार्निवल एमपीवी की नई जेनरेशन को लॉन्च किया गया है। इस प्रीमियम एमपीवी की भारत में काफी ज्यादा मांग है। कंपनी से जानकारी मिली है कि लॉन्च के बाद दो महीने में ही इसकी 400 यूनिट्स की डिलीवरी की जा चुकी है।

कितना है वेटिंग पीरियड: किआ की ओर से बताया गया है कि इस गाड़ी को अगर आज बुक करवाया जाता है तो छह महीने से ज्यादा का इंतजार डिलीवरी (Kia Carnival waiting period) के लिए करना होगा। बुकिंग शुरू होने के बाद से अब तक इसके लिए 3350 यूनिट्स की बुकिंग हो चुकी है।

कैसे हैं फीचर्स: किआ की ओर से कार्निवल की नई जेनरेशन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। इसमें ड्यूल सनरूफ, 12.3 इंच कर्व्ड डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, स्मार्ट पावर स्लाइडिंग डोर, रियर एलईडी कॉम्बिनेशन लैंप, फ्रंट एलईडी फॉग लैंप, सेकेंड रो पावर्ड सीट्स के साथ वेंटिलेशन, बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम और 12 स्पीकर्स, वायरलैस फोन चार्जर, हेड-अप डिस्प्ले, 18 इंच अलॉय व्हील्स, थ्री जोन फुली ऑटोमैटिक टेंपरेचर कंट्रोल, आठ एयरबैग, रियर क्रॉस ट्रैफिक कॉलिजन अवाइडेंस सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं।

कक्षाओं में परिवर्तन:राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-संरेखित शिक्षा

विजय गर्ग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ)। फाउंडेशनल से लेकर माध्यमिक तक सभी स्तरों के लिए विकसित, न्यू डायरेक्शन्स केंद्रित सामग्री, कौशल-निर्माण अभ्यास और उन्नत डिजिटल टूल के साथ कक्षा सीखने में क्रांतिकारी बदलाव लाता है। शैक्षणिक उत्कृष्टता और विश्वसनीय शिक्षण संसाधनों के प्रति विवा एजुकेशन की प्रतिबद्धता ने देश भर में शिक्षा को आकार दिया है। नई दिशाओं के साथ, यह छात्रों को अकादमिक और उससे आगे सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करके सीखने को फिर से परिभाषित करता है। नई दिशाओं की मुख्य विशेषताएं: 1. एनईपी और एनसीएफ संरेखित पाठ्यक्रम विवा एजुकेशन की नई दिशाएँ श्रृंखला सीखने के लिए एक आधुनिक और समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) के उद्देश्यों के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। किताबें 'कम सामग्री, अधिक सीखने' पर ध्यान केंद्रित करती हैं, अनावश्यक जटिलता को कम करती हैं और छात्रों को आवश्यक अवधारणाओं के साथ गहराई से जुड़ने में सक्षम बनाती हैं। प्रत्येक पुस्तक को विषयों को सरल बनाने, बेहतर वैचारिक समझ को बढ़ावा देने और ज्ञान प्रतिधारण सुनिश्चित करने के लिए संरचित किया गया है। 2. कौशल-आधारित शिक्षा श्रृंखला कौशल विकास पर जोर देती है, संचार, सहयोग और आलोचनात्मक सोच जैसी 21वीं सदी की दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। श्रृंखला की प्रत्येक पुस्तक में इन आवश्यक कौशलों को बढ़ाने के लिए गतिविधियाँ और अभ्यास हैं। इनमें समस्या-समाधान परिदृश्य, समूह चर्चा और महत्वपूर्ण सोच कार्य शामिल हैं जो पारंपरिक पाठ्यपुस्तक सामग्री से परे हैं। 3. अंतःविषय शिक्षण और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एनईपी सभी विषयों और पाठ्यक्रम में अंतःविषय दृष्टिकोण की सिफारिश करता है। उदाहरण के लिए, श्रृंखला न्यू डायरेक्शन इंग्लिश में विशेष गतिविधियाँ हैं जो शिक्षार्थियों को अन्य विषयों, अनुशासनों और डोमेन के संदर्भों में लागू करके पाठ्य विचारों का विस्तार करने और उनका पता लगाने में मदद करती हैं। यह श्रृंखला संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को भाषा पाठ्यक्रम में इस तरह से एकीकृत करती है जो जागरूकता पैदा करती है और कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है। 4. वास्तविक दुनिया की प्रासंगिकता न्यू डायरेक्शन पाठ्यक्रम में बहु-विषयक पाठ शामिल हैं जो विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को वास्तविक जीवन के परिदृश्यों से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, किताबों में गणित के पाठों में बजट बनाने के अभ्यास शामिल होते हैं, जबकि विज्ञान के विषयों में पर्यावरण संरक्षण का पता लगाया जाता है। प्रत्येक अध्याय अमूर्त अवधारणाओं और उनके रोजमर्रा के अनुप्रयोगों के बीच अंतर को पाटने के लिए व्यावहारिक उदाहरण और गतिविधियाँ प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण छात्रों को उनकी शिक्षा की प्रासंगिकता देखने में मदद करता है और सीखने को सार्थक और प्रभावशाली बनाकर समझ और धारणा में सुधार करता है। 5. सांस्कृतिक एकता किताबें वैश्विक दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाती हैं। पाठों को देश की परंपराओं, इतिहास और मूल्यों पर गर्व पैदा करने, मजबूत सांस्कृतिक जागरूकता और राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही, श्रृंखला वैश्विक दृष्टिकोण को शामिल करके छात्रों के क्षितिज को व्यापक बनाती है, यह सुनिश्चित करती है कि वे अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार हैं। भारतीय और वैश्विक संस्कृतियों को प्रतिबिंबित करने वाली कहानियों, उदाहरणों और गतिविधियों को एकीकृत करके, किताबें संतुलित व्यक्तियों का निर्माण करती हैं जो नवाचार को अपनाने के साथ-साथ परंपरा की सराहना करते हैं। 6. इंटरएक्टिव और समावेशी गतिविधियाँ नई दिशाएं विविध शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए पूछताछ-आधारित अभ्यास, व्यावहारिक परियोजनाएं और सहयोगी गतिविधियां प्रदान करती हैं। ये इंटरैक्टिवतत्व छात्रों को सक्रिय सीखने में संलग्न करते हैं, जिससे कक्षा अधिक समावेशी और मनोरंजक बन जाती है। पुस्तकों में विशिष्ट अनुभाग विभिन्न सीखने की प्राथमिकताओं को संबोधित करते हैं, जो अद्वितीय आवश्यकताओं वाले छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए पहुंच सुनिश्चित करते हैं। पुस्तकों में भागीदारी बढ़ाने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए दृश्य सहायता, निर्देशित अभ्यास और समूह-

आधारित कार्य भी हैं। 7. उन्नत डिजिटल उपकरण विवा एआई-बडी, एक एआई-संचालित शिक्षण सहायक, अनुरूप अभ्यास, त्वरित प्रतिक्रिया और इंटरैक्टिव समर्थन के साथ सीखने के अनुभव को वैयक्तिकृत करता है। आसान पहुंच के साथ, छात्र अपनी वाइवा एजुकेशन पाठ्यपुस्तक से जुड़े ऐप या प्लेटफॉर्म तक पहुंच कर, दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके और एआई असिस्टेंट के साथ बातचीत करके वाइवा एआई-बडी का उपयोग कर सकते हैं। वे प्रश्न पूछ सकते हैं, अवधारणा सारांश का अनुरोध कर सकते हैं, एनिमेटेड स्पष्टीकरण देख सकते हैं या अपनी समझ का परीक्षण करने के लिए अभ्यास क्विज़ ले सकते हैं। उच्च-गुणवत्ता वाले एनिमेशन, व्याख्याकार वीडियो और डिजिटल अभ्यास पाठ को संलग्न करते हैं, रुचि और समझ को बढ़ाते हैं। 8. समग्र विकास शिक्षाविदों से परे, पुस्तकों में मूल्यों की शिक्षा, भावनात्मक कल्याण और सामाजिक जागरूकता के पाठ शामिल हैं। अध्यायों में सहानुभूति, लचीलापन और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए गतिविधियाँ और परिदृश्य शामिल हैं। यह समग्र दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि छात्र कक्षा से परे चुनौतियों का सामना करने में सक्षम पूर्ण व्यक्ति के रूप में विकसित हों। श्रृंखला छात्रों को भावनात्मक संतुलन और सामाजिक जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करके विभिन्न परिस्थितियों में अखंडता और अनुकूलनशीलता बनाए रखने के लिए तैयार करती है। चिरायु के बारे में विवा एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम है, जो छात्रों और शिक्षकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संसाधन बनाने के लिए समर्पित है। 35 वर्षों से अधिक की प्रकाशन विशेषज्ञता के साथ, विवा एजुकेशन, विवा बुक्स का एक प्रभाग, मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तरों के लिए नवीन, आकर्षक और पाठ्यक्रम-संरेखित सामग्री प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाने वाला, विवा एजुकेशन ऐसी किताबें विकसित करता है जो अकादमिक कठोरता को व्यावहारिक शिक्षा के साथ जोड़ती हैं, महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और कौशल विकास को बढ़ावा देती हैं। डिजिटल टूल और एआई-संचालित समाधानों सहित पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक तकनीक के मिश्रण के साथ, विवा एजुकेशन सीखने के भविष्य को आकार दे रहा है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

वार्षिक पत्रिका शिक्षण संस्थान के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज है

विजय गर्ग

विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का एक रोचक एवं महत्वपूर्ण समय होता है। आज, अनिवार्य स्कूली शिक्षा के समान अवसर ने हर बच्चे को स्कूल तक ला दिया है। माता-पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके सफल इंसान बनें। व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान अपने मानकों को बनाए रखने के लिए नई तकनीकों, इंटरनेट, शिक्षा विशेषज्ञों के व्याख्यान, मनोवैज्ञानिकों की सलाह, विकसित देशों के शिक्षा मॉडल का उपयोग करते हैं।फॉलो आदि करते रहते हैं। आजकल प्रिंट/ऑडियो/वीडियो मीडिया और सोशल साइट्स के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ये संस्थान अपने छात्रों के लिए संस्थान की वार्षिक पत्रिका सहित विभिन्न सुविधाओं या पहलों की व्यवस्था भी करते हैं। इंटरनेट के आगमन से पहले, शैक्षणिक संस्थान और वार्षिक पत्रिकाएँ एक दूसरे के पूरक थे। विद्यार्थी और शिक्षक पत्रिका के प्रकाशन का बेसब्री से इंतजार करते थे। अब इंटरनेट पर पत्रिकाओं की जगह सोशल साइट्स लेती जा रही हैं। उनकी अपनी उपयोगिता पी होगीशिक्षण संस्थानों की पत्रिकाओं के झंडे आज भी लहरा रहे हैं। ये पत्रिकाएँ, जिन्हें पत्रिकाएँ भी कहा जाता है, उनके शैक्षणिक संस्थान यानी कॉलेज, विश्वविद्यालय या स्कूल की एक खिड़की हैं। इसके माध्यम से सत्र के दौरान उस संस्थान की शैक्षणिक, खेल-कूद, सह-शैक्षणिक गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक एवं अन्य आयोजनों तथा कई अन्य गतिविधियों का विवरण कुछ पन्नों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। इन गतिविधियों की तस्वीरें सोने पर खूबसूरती से चित्रित की गई हैं। उपरोक्त गतिविधियों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के चित्र कहाँइससे उन्हें बेहद खुशी होती है और अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिलती है। कहते हैं, 'गुरु बिनु गत नहीं, शाह बिनु पात।' ऐतिहासिक दस्तावेज़ नवोदित छात्रों, लेखकों के व्यक्तिगत कार्य रोचक, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद हैं। पत्रिका में पृष्ठों की सीमा के कारण साहित्यिक कृतियों विशेषकर निबंध, कहानियाँ, लघु यात्रा वृतांत तथा शोध पत्रों में संक्षिप्तता का गुण होना चाहिए। यह पत्रिका कई लेखकों के लिए साहित्य के क्षेत्र में पहला कदम भी हो सकती है। संगठन की वार्षिक पत्रिका की अगली विशेषता उसका अपना संगठन हैएक ऐतिहासिक दस्तावेज़ प्रकाशित किया जाना है. आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय वर्तमान जानकारी पिछले संस्करणों से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा संस्था का पत्रिका से भावनात्मक जुड़ाव भी है. यदि यह पत्रिका थोड़े या लम्बे समय के बाद हमारे हाथ में रह जाती है तो यह हमें हमारे विद्यार्थी जीवन में वापस ले जाती है। रचनात्मक कला से युक्त पत्रिकाएँ स्कूल शिक्षा विभाग की यह एक बड़ी पहल है कि हर साल बाल दिवस के अवसर पर प्रत्येक सरकारी स्कूल की वार्षिक पत्रिका का विमोचन किया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों का अपनाहाथ से बनाई गई पेंटिंग और अन्य रचनात्मक कला से एक पत्रिका बनाएं। महाविद्यालयों जैसे बड़े विद्यालयों में संपादक एवं सम्पादक मंडल नियमित रूप से पत्रिका प्रकाशित कर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी, लेखक और पाठक,

विद्यालय और पत्रिका के बीच सहयोग का महत्व बना रहना चाहिए। उपलब्धि की ओर शिक्षक नेतृत्व शिक्षकों का अच्छा मार्गदर्शन छात्रों को महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर ले जाता है। अपने छात्रों की सफलता से शिक्षकों को खुशी और गर्व महसूस होता है। इस प्रकार वार्षिक पत्रिका विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों के लिए समान महत्व रखती है. पत्रिकाएँ पाठकों को साहित्य से जोड़े रखती हैं। मोबाइल फोन के असीमित उपयोग या अन्य व्यस्तताओं के कारण लोग साहित्य से दूर होते जा रहे हैं। पाठकों की कमी के कारण लेखकों को उचित प्रतिक्रिया और आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। साहित्य से मार्गदर्शन पाने के लिए साहित्य से जुड़ना बहुत जरूरी है। इससे लेखकों को उनका उचित सम्मान भी मिलता है. लेखक और पाठक अपनी मातृभाषा के साथ-साथ अन्य भाषाओं से भी जुड़े रहते हैं।

जलवायु परिवर्तन से बचना कठिन होता जा रहा है

विजय गर्ग

विश्व मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, इस साल वायुमंडल का औसत तापमान औद्योगिकीकरण से पहले के तापमान की तुलना में 1.54 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है. ग्लोबल वार्मिंग के कारणों की जांच करने और इसे रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1996 से आयोजित किया जा रहा है। 2015 के पेरिस शिखर सम्मेलन में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए सभी संभव उपाय करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि अगर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बंद कर दिया गयायदि नहीं, तो 2028 तक तापमान 1.5 डिग्री से अधिक हो जाएगा, जिसके बाद सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी आपदाओं से निपटना और तापमान वृद्धि को रोकना और अधिक कठिन हो जाएगा। सदस्य देशों ने अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयास किये हैं, लेकिन तापमान वृद्धि की गति से पता चलता है कि वे अपर्याप्त रहे हैं। अज़रबैजान की राजधानी बाकू में हाल ही में संपन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में केवल दो उल्लेखनीय समझौते हो सके। पहला कार्बन क्रेडिट योजना पर था, जो लगभग दस वर्षों से लंबित थी। दूसरा हवा-पानीपरिवर्तन की रोकथाम के लिए वित्तीय सहायता पर। वह भी इस डर से कि अमेरिका की बागडोर जलवायु परिवर्तन को महत्व नहीं देने वाले ट्रंप के हाथों में जा रही है. इसमें विकासशील देश चाहते थे कि तापमान को मौजूदा स्तर पर लाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले विकसित देश उन्हें स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए सालाना कम से कम 1300 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देना शुरू करें, लेकिन अमीर देश रो रहे हैं सालाना सिर्फ 300 अरब डॉलर देने को तैयार वो भी 2035 से. अमीर देशों का कहना है कि प्रस्तावित राशि मौजूदा 100 अरब डॉलर हैउससे तीन गुना, इसलिए विकासशील देशों को नाराज़ होने के बजाय ख़ुश होना चाहिए, लेकिन

विकासशील देशों का कहना है कि यह ज़रूरत का एक चौथाई भी नहीं है. इसीलिए भारत की प्रतिनिधि चांदनी रैना ने इसे ऊंट के मुंह में तिनका बताया. उन्होंने कहा कि यह समझौता मृगतृष्णा से ज्यादा कुछ नहीं है. इससे इस गंभीर चुनौती का सामना करने में कोई खास मदद नहीं मिलेगी. विकासशील एवं छोटे गरीब देशों ने इस सम्मेलन की कड़ी आलोचना की। हर साल जलवायु शिखर सम्मेलन में किए गए समझौते और बड़े वादेइसके बावजूद तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से पता चलता है कि या तो अब तक उठाए गए कदम अपर्याप्त हैं या फिर उन्हें ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा है। स्टैनफोर्ड में पढ़ाने वाले आर्थिक इतिहासकार वाल्टर डेल की प्रसिद्ध पुस्तक 'द ग्रेट लेवलर' के अनुसार, मानव इतिहास में वास्तविक परिवर्तन हमेशा बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के कारण हुए हैं। जलवायु परिवर्तन को बड़े पैमाने पर विनाश की ओर ले जाने से रोकने के लिए ठोस और तीव्र उपाय करने के बजाय हर साल होने वाली अंतहीन बातचीत शीडेल को सही साबित करती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है किजलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सहमति किसी अन्य मुद्दे पर कभी नहीं बन पाई है। इसीलिए बिल गेट्स का मानना है कि हम एक ऐसे युग समझौते पर पहुंच गए हैं जो इतिहास बदल देगा। नई और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास से जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बड़ी आपदाओं की रोकथाम हो सकेगी। सौर, पवन, जल और परमाणु से स्वच्छ ऊर्जा की लागत में तेजी से गिरावट और साथ ही कम ऊर्जा खपत करने वाले वाहनों और मशीनों के विकास के साथ, बिल गेट्स के शब्द विश्वसनीय हैं, लेकिन जयईंधन से चलने वाले वाहनों, कारखानों और बिजली संयंत्रों को स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली में बदलने के लिए आवश्यक 11,000 अरब डॉलर का निवेश कहां और कैसे आएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बाकू में 2035 से 300 अरब डॉलर की सालाना मदद का वादा किया गया है. क्या तब तक तापमान स्थिर रहेगा? विकसित देशों ने भी विकासशील देशों से आयात पर कार्बन कर लगाना शुरू कर दिया है। यूरोपीय संघ के कार्बन कैप समायोजन तंत्र से भारत जैसे देशों में निर्यातकों के लिए लागत बढ़ जाएगी। इसीलिए विकसित देशबढ़ते तापमान में अपनी भूमिका की याद दिलाते हुए वित्तीय सहायता के लिए दबाव बनाए रखने के अलावा, चीन जैसे विकासशील देशों को जलवायु की रक्षा के लिए स्वयं प्रभावी उपाय करने होंगे। सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश बनने के साथ-साथ चीन स्वच्छ ऊर्जा और उस पर आधारित प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा उत्पादक भी बन गया है। उन्होंने विकसित देशों का मुंह बंद रखने के लिए आर्थिक सहायता में योगदान देने की पहल भी की है. एक तिहाई ग्रीनहाउस गैसें खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण और आपूर्ति से जुड़े उद्योगों से आती हैंहो रहे हैं, जिनकी रोकथाम पर गंभीरता से चर्चा तक नहीं हो रही है। विश्व के जैव ईंधन का लगभग 15 प्रतिशत कृषि और उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उत्पादन में खपत होता है। घरेलू पशुओं द्वारा उत्सर्जित मीथेन गैस भी तापमान वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता है। खाद्य प्रसंस्करण, प्रशीतन, पैकेजिंग और आपूर्ति उद्योग भी जैव ईंधन पर चलते हैं। स्वच्छ ऊर्जा के साथ कृषि चलाने और आयातित खाद्य पदार्थों के बजाय ताजा और मौसमी खाद्य पदार्थों और मांस के बजाय शाकाहार को प्रोत्साहित करने से, लगभग एक तिहाई ग्लोबल वार्मिंग गैसों से बचा जा सकता है।लेकिन विकसित और विकासशील देशों में किसान और खाद्य उद्योग इतने संगठित हैं कि किसी भी सरकार के पास इतने बड़े बदलावों के लिए उन पर दबाव बनाने की इच्छाशक्ति नहीं है। भारत में इस तथ्य के बावजूद कि दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत हर साल एसिड कोहरे की चादर से ढका रहता है, यह न तो चुनावों में मुख्य मुद्दा बन पाता है और न ही संसद में इस पर कोई सार्थक चर्चा होती है। 1950 के आसपास लंदन का वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI दिल्ली से भी बदतर हुआ करता था। आज दिल्ली की जीडीपी से कई गुना ज्यादा देने के बावजूद लंदन का AQI औसत है20 पर कोई नहीं रहता और दिल्ली 150 पर जो अक्टूबर में 400 को पार कर जाता है। 2013 में बीजिंग का AQI 600 और सिंगापुर का 400 पार कर गया था. आज बीजिंग और सिंगापुर दोनों का AQI दिल्ली से काफी कम है। जनता कमर कस ले तो क्या नहीं हो सकता? सिर्फ सरकारों का मुंह देखने से समस्या का समाधान नहीं होगा। लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति जागरूक होना चाहिए और इसके कारणों के समाधान के लिए आगे आना चाहिए। लोगों को पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली आदतों को छोड़ना होगा। पर्यावरण को बनाए रखने के लिएसरकारों द्वारा बनाए गए नियम-कायदों का सख्ती से पालन करना होगा। तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जब सरकारी और निजी स्तर पर हर कोई कमर कस लेगा तो स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगी।

कहानी : ईमानदारी

विजय गर्ग

एक राहुल नाम का व्यक्ति था, स्वभाव से बहुत ही गंभीर था, उसकी पढाई पूरी हो चुकी थी लेकिन कोई नौकरी नहीं थी । दिन रात वो काम की तलाश में इधर – उधर भटकता रहता था । राहुल एक ईमानदार मनुष्य भी था इसलिये भी उसे काम मिलने में मुश्किल आ रही थी। दिन इतने ख़राब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ी , रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था । राहुल पढ़ा लिखा था जो उसके व्यवहार से साफ जाहिर होता था । एक दिन एक सेठ के घर राहुल मजदूरी कर रहा था , सेठ का ध्यान राहुल के उपर ही था , सेठ को समझ आ रहा था कि राहुल एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का हैं लेकिन परिस्थती वश उसे ऐसे मजदूरी वाला काम करना पड़ रहा हैं । सेठ को अपने एक विशेष काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरुरत थी, उसने राहुल की परीक्षा लेने की सोची । उसने एक दिन राहुल को अपने पास बुलाया और उसे पचास हजार रूपये दिए जिसमे सो-सो के नोट थे और कहा भाई तुम ईमानदार लगते हो ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ । राहुल ने ईमानदारी से पैसे पहुँचा दिए । दुसरे दिन, व्यापारी ने राहुल को फिर से पैसे दिए इस बार उसने राहुल को बिना गिने पैसे दिए कहा खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ । राहुल ने ईमानदारी से काम किया ।सेठ पहले से ही गल्ले में पैसे गिनकर रखता था पर वो राहुल की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था ,रोज वो सेठ उसे पैसे देने भेजता था । राहुल की माली हालत तो बहुत ही ख़राब थी । एक दिन उसकी नियत डोल गयी और उसने सौ रूपये चुरा लिए जिसका पता सेठ को लग गया पर सेठ ने कुछ नहीं कहा । फिर से राहुल को रूपये देने भेजा । सेठ के कुछ न कहने पर राहुल की हिम्मत बढ़ गयी , उसने रोजाना चोरी शुरू कर दिया । सेठ को उम्मीद थी कि राहुल उसे सच बोलेगा लेकिन राहुल ने नहीं बोला । एक दिन सेठ ने राहुल को काम से निकाल दिया । वास्तव में सेठ अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था, उसकी कोई संतान नहीं थी , राहुल को भोला भाला जानकर उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची थी , अगर राहुल सच बोलता तो सेठ उसे अपनी दुकान सौप देता। जब राहुल को इस बात का पता चला हैं तो उसे बहुत दुःख हुआ और उसने स्वीकारा कि कैसी भी परिस्थती हो ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति होती हैं ।

शिक्षा*

दोस्तों कैसा भी मुकाम आये व्यक्ति को ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए । ईमानदारी जीवन की वो कमाई हैं जो मुश्किल हैं लेकिन कभी गलत अंत नहीं

स्टील की डिमांड में आएगा बड़ा उछाल, क्या ग्रीन स्टील से पूरी होगी जरूरत?

परिवहन विशेष न्यूज

अभी दुनिया के किसी देश ने ग्रीन स्टील की परिभाषा तय नहीं की है लेकिन स्टील मंत्रालय की तरफ से ग्रीन स्टील की परिभाषा तय कर दी गई है और इस प्रकार ग्रीन स्टील में भारत वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। अभी देश में 18 करोड़ स्टील उत्पादन की क्षमता है। 12 करोड़ टन की उत्पादन क्षमता तैयार करने के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश करना होगा।

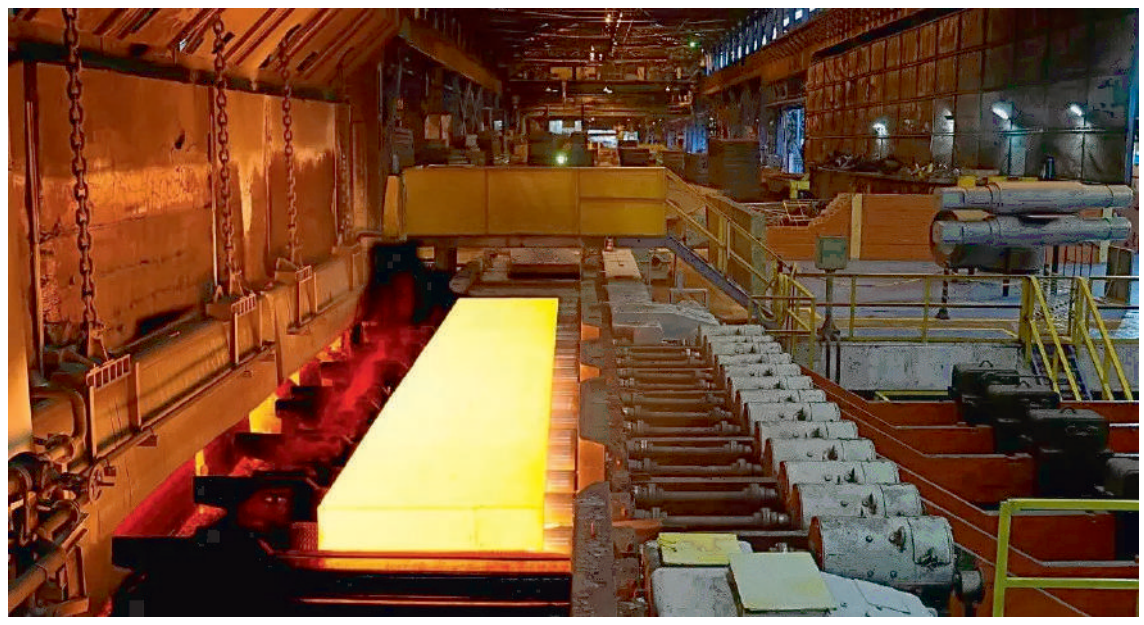

नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए वर्ष 2030 तक देश में सालाना 30 करोड़ टन स्टील की खपत का अनुमान लगाया जा रहा है। स्टील मंत्रालय के मुताबिक ऐसे में अगले छह साल में स्टील उत्पादन में 12 करोड़ टन की बढ़ोतरी की आवश्यकता होगी।

अभी देश में 18 करोड़ स्टील उत्पादन की क्षमता है। 12 करोड़ टन की उत्पादन क्षमता तैयार करने के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश करना होगा। मंत्रालय इस क्षमता का विस्तार ग्रीन स्टील से करने जा रहा है। अभी दुनिया के किसी देश ने ग्रीन स्टील की परिभाषा तय नहीं की है, लेकिन स्टील मंत्रालय की तरफ से ग्रीन स्टील की परिभाषा तय कर दी गई है और इस प्रकार ग्रीन स्टील में भारत वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है।

स्टील सेक्टर भी कार्बन उत्सर्जन का जिम्मेदार

मंत्रालय चाहता है कि वर्ष 2030 से देश में सिर्फ ग्रीन स्टील का उत्पादन हो। हालांकि अभी इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है, लेकिन पूरी तैयारी इसी दिशा में हो रही है। गुरुवार को स्टील मंत्री एच.डी कुमारस्वामी ने ग्रीन स्टील की परिभाषा को सार्वजनिक किया। दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन में स्टील सेक्टर की हिस्सेदारी सात प्रतिशत है।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक 12 करोड़ टन ग्रीन स्टील के उत्पादन के क्षमता विस्तार के लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) स्कीम से इसे जोड़ने पर विचार कर रही है। विशेष प्रकार के स्टील (स्पेशल स्टील) के उत्पादन को लेकर सरकार पहले ही पीएलआई स्कीम ला चुकी है।

ग्रीन स्टील की मांग में बढ़ोतरी के लिए मंत्रालय स्टील की सरकारी खरीद में 37 प्रतिशत ग्रीन स्टील की खरीदारी को अनिवार्य कर सकती है। कुमारस्वामी ने कहा कि भारत दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। ग्रीन स्टील के उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व देना चाहता है।

क्या होगा ग्रीन स्टील (green steel)

बिजली खपत के आधार पर जैसे एसी और फ्रिज की रेटिंग की जाती है, वैसे ही ग्रीन स्टील की रेटिंग की जाएगी। एक टन स्टील के फिनिश्ड प्रोडक्ट के निर्माण में 2.2 टन से कम कार्बन उत्सर्जन पर उसे ग्रीन स्टील माना जाएगा। अगर कार्बन उत्सर्जन 1.6 टन से कम है तो उसे फाइव स्टार रेटिंग, 1.6-2 टन के उत्सर्जन पर फोर स्टार रेटिंग तो 2.0-2.2 तक कार्बन उत्सर्जन होने पर थ्री स्टार रेटिंग दी जाएगी।

सुस्त पड़ी इंडसट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ; माइनिंग-मैन्युफैक्चरिंग के खराब प्रदर्शन का दिखा असर

परिवहन विशेष न्यूज

अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि दर घटकर 4.1 प्रतिशत रह गई जो एक साल पहले की समान अवधि में 10.6 प्रतिशत थी। इसी तरह बिजली उत्पादन में उत्पादन वृद्धि दर एक साल पहले के 20.4 प्रतिशत से घटकर दो प्रतिशत रह गई। कैपिटल गुड्स की वृद्धि दर अक्टूबर 2024 में घटकर 3.1 प्रतिशत रह गई जो एक साल पहले इसी अवधि में 21.7 प्रतिशत थी।

नई दिल्ली। खनन, बिजली और मैन्युफैक्चरिंग के खराब प्रदर्शन के चलते अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) की वृद्धि सालाना आधार पर नरम पड़कर 3.5 प्रतिशत रह गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर 2023 में आइआइपी में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

हालांकि, क्रमिक आधार पर अक्टूबर, 2024 में कारखाना उत्पादन सितंबर के 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो गया। इस साल अगस्त में 0.1 प्रतिशत का संकुचन हुआ था। आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-अक्टूबर में आईआईपी के संदर्भ में मापा गया कारखाना उत्पादन में वृद्धि एक साल पहले के सात प्रतिशत के मुकाबले चार प्रतिशत रही। आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में खनन उत्पादन की वृद्धि एक साल पहले के 13.1 प्रतिशत विस्तार से घटकर 0.9 प्रतिशत रह गई।

अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि दर घटकर 4.1 प्रतिशत रह गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 10.6 प्रतिशत थी। इसी तरह, बिजली उत्पादन में उत्पादन वृद्धि दर एक साल पहले के 20.4 प्रतिशत से घटकर दो प्रतिशत रह गई।

कैपिटल गुड्स की वृद्धि दर अक्टूबर, 2024 में घटकर 3.1 प्रतिशत रह गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 21.7 प्रतिशत थी। आंकड़ों के अनुसार, बुनियादी ढांचे/निर्माण वस्तुओं में अक्टूबर, 2024 में चार प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम है।

आंकड़ों से यह भी पता चला कि प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में इस वर्ष अक्टूबर में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पूर्व इसी माह में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि इस साल अक्टूबर में घटकर 3.5 प्रतिशत रह गई।

इसका मुख्य कारण खनन, बिजली और विनिर्माण क्षेत्रों का खराब प्रदर्शन है। गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संदर्भ में मापा जाने वाला कारखाना उत्पादन पिछले साल इसी महीने में 11.9 प्रतिशत की दर से बढ़ा था।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि देश का औद्योगिक उत्पादन अक्टूबर, 2024 में 3.5 प्रतिशत बढ़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन अक्टूबर, 2024 में 4.1 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एक साल पहले इसी महीने में इसमें 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

अक्टूबर, 2024 में खनन उत्पादन में 0.9 प्रतिशत और बिजली उत्पादन में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल-अक्टूबर की अवधि में, आईआईपी में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में औद्योगिक उत्पादन सात प्रतिशत बढ़ा था।

जनता को बड़ी राहत; सब्जी, फल और दूध के घटे दाम; 5.48 फीसदी रही खुदरा महंगाई

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के डेटा के अनुसार नवंबर में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति घटकर 9.04 प्रतिशत रह गई। अक्टूबर में यह 10.87 प्रतिशत और नवंबर 2023 में 8.70 प्रतिशत थी। एनएसओ ने कहा कि नवंबर 2024 के दौरान सब्जी दाल चीनी फल अंडा दूध मसाले परिवहन और संचार की मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।

नई दिल्ली। आम जनता को नवंबर में महंगाई से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में घटकर 5.48 प्रतिशत पर आ गई। यह अक्टूबर में 6.21 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई थी। ऐसा मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खासकर सब्जियों के भाव में नरमी के कारण हुआ।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के डेटा के अनुसार, नवंबर में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति घटकर 9.04 प्रतिशत रह गई। अक्टूबर में यह 10.87 प्रतिशत और नवंबर 2023 में 8.70 प्रतिशत थी। एनएसओ ने कहा, ₹नवंबर 2024 के दौरान सब्जी, दाल, चीनी, फल, अंडा, दूध, मसाले, परिवहन और संचार की मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।₹

पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को 4.5 फीसदी से बढ़ाकर 4.8 फीसदी कर दिया। इसने यह भी कहा था कि खाद्य कीमतों के दबाव के कारण दिसंबर तिमाही में हेडलाइन इन्फ्लेशन के ऊंचे रहने की संभावना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित हेडलाइन इन्फ्लेशन जुलाई-अगस्त के दौरान औसतन 3.6 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 5.5 प्रतिशत और अक्टूबर 2024 में 6.2 प्रतिशत हो गई।

महंगाई से राहत, खाने-पीने की चीजों के घटे दाम; क्या अब आरबीआई ब्याज दरों में करेगा कटौती?

परिवहन विशेष न्यूज

आम जनता के लिए राहत वाली खबर आई है। नवंबर में खुदरा महंगाई कम होकर 5.48 फीसदी पर आ गई। यह अक्टूबर 6.21 फीसदी थी। आर्थिक जानकारों का मानना है कि अगर आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई में नरमी बनी रहती है तो मौद्रिक नीति कमेटी की आगामी बैठक में आरबीआई ब्याज दरों में मामूली कटौती कर सकता है। आरबीआई महंगाई दर को चार प्रतिशत तक लाना चाहता है।

नई दिल्ली। खुदरा महंगाई में थोड़ी राहत मिली है। गत नवंबर में खुदरा महंगाई की बढ़ोतरी दर पिछले साल नवंबर के मुकाबले 5.48 प्रतिशत रही जबकि इस साल अक्टूबर में खुदरा महंगाई में 6.21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। नवंबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर भी थोड़ी नरमी के साथ 9.04 प्रतिशत रही जबकि अक्टूबर में यह दर 10.87 प्रतिशत थी।

आगामी जनवरी तक महंगाई दर में नरमी जारी रही, तो फरवरी में आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। दिसंबर में मौद्रिक नीति कमेटी ने महंगाई दर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए ही ब्याज दरों में किसी कटौती से साफ इन्कार कर दिया था। आरबीआई ने महंगाई की अधिकतम सीमा छह प्रतिशत तय कर रखा है। हालांकि आरबीआई महंगाई दर को चार प्रतिशत तक लाना चाहता है।

किस वजह से नवंबर में घटी महंगाई?

नवंबर में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर नौ प्रतिशत और कुल महंगाई दर के पांच प्रतिशत से ऊपर रहने के लिए सब्जी और खाद्य तेल के दाम मुख्य रूप से जिम्मेदार है। नवंबर में सब्जी के दाम में पिछले साल नवंबर की तुलना में 29.33 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

इस बढ़ोतरी में आलू, फूलगोभी, पत्ता गोभी व लहसुन का मुख्य हाथ है। आलू की खुदरा कीमतों में पिछले साल नवंबर की तुलना में 66.65 प्रतिशत, फूलगोभी में 47.70 प्रतिशत, पत्ता गोभी में 43.58 प्रतिशत, नारियल तेल में 42.13 प्रतिशत तो लहसुन के दाम में 85.14 प्रतिशत का इजाफा रहा।

नवंबर में खाद्य तेल की कीमतों में 13.28 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। आनंद राठी ग्रुप के मुख्य अर्थशास्त्री सुजान हज़ के मुताबिक आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई में नरमी का रुख रहने की संभावना है। रबी की अच्छी फसल की संभावना से खाद्य वस्तुओं की कीमतें भी कम होंगी। ऐसा हुआ तो मौद्रिक नीति कमेटी की आगामी बैठक में ब्याज दरों में मामूली कटौती हो सकती है।

किन राज्यों में कितनी रही महंगाई दर

नवंबर में देश भर की खुदरा महंगाई 5.48 प्रतिशत रही, लेकिन दिल्ली में यह महंगाई दर सिर्फ 2.65 प्रतिशत रही जो देश के सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में महंगाई दर सबसे अधिक 8.39 प्रतिशत रही। बिहार में महंगाई दर 7.55 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 6.56 प्रतिशत, हरियाणा में 5.32 प्रतिशत, उत्तराखंड में 5.34 प्रतिशत, पंजाब में 4.68 प्रतिशत, झारखंड में 5.41 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 5.13 प्रतिशत तो मध्य प्रदेश में 6.05 प्रतिशत रही।

GST घटे तो रफ्तार पकड़ेगी फुटवियर इंडस्ट्री, क्या बजट में मिलेगी सौगात?

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली सीमा से लगे हरियाणा के बहादुरगढ़ में देश का सबसे बड़ा नॉन-लेदर फुटवियर पार्क है। कई नामी कंपनियां यहां फुटवियर तैयार करती हैं। उद्यमियों का कहना है कि पहले एक हजार रुपये तक का फुटवियर टैक्स फ्री था। अब 12 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ रहा है। इंडस्ट्री जीएसटी दर को पांच प्रतिशत करने की मांग कर रही है ताकि फुटवियर की डिमांड बढ़ सके।

बहादुरगढ़। भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ तेजी से दौड़ लगाने वाले फुटवियर उद्योग की रफ्तार अब सुस्त हो गई है। इसका कारण जीएसटी दर में वृद्धि है, जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने वाले फुटवियर उद्योग की राह में रोड़े अटका रही है। ड्यूटी ड्रॉ बैक कम मिलने से भी फुटवियर उद्योग में 30 प्रतिशत की गिरावट आई है।

दिल्ली सीमा से लगे हरियाणा के बहादुरगढ़ में देश का सबसे बड़ा नॉन-लेदर फुटवियर पार्क है। कई नामी कंपनियां यहां फुटवियर तैयार करती हैं। उद्यमियों का कहना है कि पहले एक हजार रुपये तक का फुटवियर टैक्स फ्री था। अब 12 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ रहा है। जीएसटी दर पांच प्रतिशत हो जाए तो बहादुरगढ़ में बने फुटवियर की मांग ज्यादा हो जाएगी।

अभी बहादुरगढ़ के फुटवियर का निर्यात करीब साढ़े तीन हजार करोड़ है। अगर सरकार प्रोत्साहन दे और ड्यूटी ड्रॉ बैक को डेढ़ प्रतिशत से बढ़ाकर छह प्रतिशत कर दे तो यहां का निर्यात सालाना दस हजार करोड़ रुपये हो जाएगा। चीन में फुटवियर पर ड्यूटी ड्रा बैक 12 प्रतिशत है। इस कारण वहां का माल दूसरे देशों में निर्यात हो रहा है। इसके अलावा चीन से आयातित फुटवियर कंपोनेंट पर 40 प्रतिशत ड्यूटी ली जाती है। इसे पांच प्रतिशत किया जाए।

बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में छोटी-बड़ी करीब ढाई हजार फैक्ट्रियां नॉन-लेदर फुटवियर बनाती हैं। यहां हर रोज करीब 80 लाख फुटवियर बनते हैं। यहां के फुटवियर उद्योग का सालाना टर्नओवर करीब 50 हजार करोड़ रुपये है। लेकिन अब यह उद्योग घाटे में चल रहा है। उद्यमियों की मानें तो पिछले तीन साल में यहां के फुटवियर की बिक्री में गिरावट आई है।

एक समय था जब देश में 80 प्रतिशत फुटवियर चीन से आयात होता था। बहादुरगढ़ में फुटवियर पार्क बनने से न केवल चीन से आयात घटकर दो प्रतिशत हो गया, बल्कि निर्यात भी होने लगा। एक हजार रुपये मूल्य तक के फुटवियर के टैक्स फ्री होने पर यह संभव हुआ था। उस समय बहादुरगढ़ के फुटवियर उद्योग ने काफी उड़ान भरी थी और हर छोटी-बड़ी इकाई मुख्यधारा में आ गई थी। मगर जीएसटी बढ़ने से फुटवियर उद्योग को काफी झटका लगा। फुटवियर उद्यमियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर जीएसटी दर घटाने की मांग भी की थी लेकिन मांग पूरी नहीं हुई है।

एक हजार फैक्ट्रियां और लगने के इंतजार मेंबहादुरगढ़ में अधिकांश फैक्ट्रियां एमएसएमई के तहत आती हैं। सरकार ने एमएसएमई से लिए माल की पेमेंट करने की अवधि 45 दिन कर दी। इससे एमएसएमई से व्यापारी माल लेना बंद कर रहे हैं। एमएसएमई के लिए पेमेंट की समयसीमा 90 से 120 दिन की जाए। साथ ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तर्ज पर सरकार जमीन लीज पर या सस्ते दामों पर मुहैया कराए तो बहादुरगढ़ में एक हजार फैक्ट्रियां और लग सकती हैं।

फुटवियर पार्क में बने कमर्शियल डिस्प्ले सेंटर

फुटवियर पार्क में एक ही तरह की फैक्ट्रियां होने से श्रमिक, कुशल श्रमिक व कर्मचारी आसानी से मिल जाते हैं। व्यापारी और सप्लायर भी एक ही जगह आ जाते हैं, जिससे व्यापार करना आसान हो जाता है। उद्यमियों के अनुसार, अगर सरकार फुटवियर पार्क में कमर्शियल और डिस्प्ले सेंटर बना दे तो देश-विदेश के सभी व्यापारी एक ही स्थान पर आ जाएंगे। इससे फुटवियर कारोबार बढ़ेगा।

अडानी ग्रुप और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में हलचल, जानिए क्या है इसकी वजह

आज ओवरऑल शेयर मार्केट में गिरावट का रुख है। लेकिन अदाणी ग्रुप के शेयरों में काफी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। वहीं बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर बीएसई पर लाल निशान में 139.20 रुपये पर खुला। यह पिछले बंद भाव से 6 प्रतिशत लुढ़ककर 132.85 रुपये के लो तक चला गया। आइए जानते हैं कि इसकी वजह क्या है।

नई दिल्ली। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में 12 दिसंबर को 6 फीसदी तक की गिरावट आई। इसकी एंकर इनवेस्टर्स के लिए 3 महीनों का लॉक-इन पीरियड खत्म होना है। इससे कंपनी के 12.6 करोड़ तक शेयर या लगभग 2 प्रतिशत इक्विटी ट्रेड के लिए फ्री हो गई। इसका मतलब है कि इनका लेनदेन हो सकेगा।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर बीएसई पर लाल निशान में 139.20 रुपये पर खुला। यह पिछले बंद भाव से 6 प्रतिशत लुढ़ककर 132.85 रुपये के लो तक चला गया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग 16 सितंबर को लिस्ट हुई थी। इसने IPO निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया था।

बजाज हाउसिंग पर ब्रोकरेज का रुख काफी मंदा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को कवर करने वाले 5 एनालिस्ट्स में से एक ने इसे 'बाय' रेटिंग दी है। वहीं 3 ने 'सेल' और एक ने 'होल्ड' रेटिंग दी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर काफी लंबे समय से अपने अपनी लिस्टिंग प्राइस यानी 150 रुपये से नीचे कारोबार कर रहा है।

अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी की वजह

आज ओवरऑल शेयर मार्केट में गिरावट का रुख है। लेकिन, अदाणी ग्रुप के शेयरों में काफी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर करीब 3 फीसदी की बढ़त के साथ 2,527.15 पर कारोबार कर रहे हैं। अदाणी पोर्ट में भी 2 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है।

अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर 7.81 फीसदी बढ़त के साथ 1,237.70 रुपये पर थे। अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस और अदाणी पावर में भी करीब 5-5 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी को छोड़कर अदाणी ग्रुप के लगभग सभी शेयर हरे निशान में हैं। अदाणी ग्रुप की कुल 10 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट हैं।

दरअसल, अदाणी ग्रीन एनर्जी ने गुरुवार को कहा कि उसकी शाखा ने राजस्थान के जोधपुर जिले के बड़ी सिड में 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। बीएसई फाइलिंग में कहा गया है कि इस संयंत्र के चालू होने के साथ, एजीईएल की कुल परिचालन अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़कर 11,434 मेगावाट हो गई है। इसी के बाद अदाणी ग्रुप की कंपनियों में पॉजिटिव मोमेंटम बना है और उनमें तेजी आई है।

बाल साहित्य की बढ़ती उपेक्षा

(कृष्ण कुमार मिश्र "अचूक-विनायक फीचर्स)

अक्सर लोगों को कहते सुना है कि बाल साहित्य भी कोई साहित्य है परंतु हमारी समझ में ऐसा कहते वही लोग हैं जिन्हें साहित्यिक क्षेत्र में कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसा कहने वाले जरा ध्यान से सोचे कि वह इतने बड़े साहित्यकार क्या बिना बाल साहित्य के पढ़े ही बन गये। साहित्य की प्रथम सीढ़ी बाल साहित्य ही है। यह कहना अनुचित न होगा कि जब उन्होंने प्रथम बार लेखनी पकड़ी होगी तो क्या सीधे गीत, गजल, कहानी, उपन्यास लिखने लगे। प्रथम तो उन्हें अ से अनार, आ से आम ही लिखना पड़ा होगा जो पूर्ण रूप से बाल साहित्य है। मानता हूं कि हाथ का अंगूठा एक महान स्तंभ होता है। बगैर उसके सहारा दिए चारों उंगली कुछ करने में समर्थ नहीं होगी। उसी प्रकार बगैर उंगलियों की सहायता के अकेला अंगूठा कुछ करने में सक्षम नहीं हो सकता है। उसी प्रकार बिना बाल साहित्य के अपनाये कोई साहित्य नहीं लिखा जा सकता।

बाल साहित्य आदिकाल से लिखा जा रहा है। उसके रूप भले ही अलग-अलग हों। गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपनी पावन लेखनी द्वारा कितना अच्छा लिखा है कि - ठुमुकि चलत रामचन्द्र बाजति पैंजनियां। वहीं महान कवि सूरदास जी ने भी अपनी पवित्र वाणी में बाल साहित्य झलकाया है। मैया कबहिं बढ़ेगी-चोटी।

हम बाल साहित्य नकारकर कोई भी साहित्य लिखने में सक्षम नहीं हो सकते। जरूरत है अच्छे बाल साहित्य की। जिससे हमारी भावी पीढ़ी को अच्छा ज्ञान संस्कार मिल सके। जब देश का बच्चा अच्छा संस्कारित होकर जागेगा तभी देश जागेगा। तभी हमारा राष्ट्र हिमालय की ऊंचाईयों पर पहुंचने में सक्षम होगा। बच्चे देश की धरोहर हैं परंतु हैं कच्ची मिट्टी। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस गीली मिट्टी से किस प्रकार की मूर्ति बनाना पसंद करते हैं। बच्चा एक दर्पण है।

दर्पण के सामने जैसी आकृति आप पैदा करेंगे वहीं प्रतिबिम्ब आपको देखने को मिलेगा। इसलिए उसके सामने महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि की ही आकृति पेश करें फिल्म सितारों की नहीं। बाल साहित्य बहुत अच्छे-अच्छे साहित्यकारों द्वारा लिखा जा चुका है और लिखा जा रहा है। आवश्यकता है उसके प्रचार और प्रसार की। सत्यता तो यह है कि जिनके लिए साहित्य लिखा गया और लिखा जा रहा है वह इन तक पहुंचता नहीं। कारण एक तो महंगाई दूसरी अभिभावकों की उदासीनता। पत्रिकायें इतनी महंगी है कि बच्चा आसानी से खरीद नहीं सकता। अभिभावक भी चाकलेट, आइस्क्रीम में दिन भर में पच्चीस पचास रूपये खर्च कर देंगे परंतु एक पत्रिका बच्चे को लेकर नहीं देंगे। वैसे बाल साहित्य प्रसार-प्रचार हेतु अनेक पत्र-पत्रिकायें प्रयासरत हैं परंतु यहां पर कर्तव्य बनता है अभिभावकों का कि वह अपनी दैनिक फिजूल खर्ची में कटौती कर बच्चों को अच्छी पत्रिकायें खरीदकर पढने को दें।

कुछ पत्र-पत्रिकायें ऐसी भी हैं जिनमें ऐसी सामग्री प्रकाशित हो रही है जिससे बच्चों को कुछ लेना देना नही। यहां हमारे संपादक महानुभावों की उदासीनता झलकती नजर आती है। ऐसी-ऐसी रचनायें प्रकाशित कर रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं। इस प्रकार की रचनायें प्रकाशित करने से पत्रिका का तो स्तर गिरता ही है साथ ही बच्चों को भी कोई प्रेरणा स्त्रोत नहीं मिलता। मैं संपादक बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि वे बच्चों को प्रेरणा से ओत-प्रोत रचनाओं को स्थान दें। साथ ही रचनाकारों से भी निवेदन करूंगा कि प्रेरणा देने वाली ही रचना रचने का प्रयास करें। आज का बच्चा कल का महान साहित्यकार बन सकता है। आज आम आदमी का कहना है कि आजकल के बच्चे मां-बाप की सेवा नहीं करते। जरा गहरी नजर से देखें इसमें गलती किसकी है। जब आपने बच्चे के अंदर मां-बाप की सेवा करने के संस्कार भरे ही नहीं फिर आप मां बाप की सेवा की अपेक्षा क्यों करते हैं।

पहले आप बच्चे के अंदर वह संस्कार भरने का प्रयास करें जिनकी आपको बच्चे से अपेक्षा है। हम करते तो यह है कि चाय-नाश्ता तैयार हुआ सभी घर के लोग पुत्र, पत्नी समेत आप नाश्ता करने लगे। मां-बाप की कोई चिंता नहीं, नाश्ता करने के बाद पुत्र से आप कहते हैं लो बेटा अपने दादा बाबा को भी चाय दे आओ कहीं पुत्र ने कह दिया कि नाश्ता भी तो दीजिए तो आप फौरन पुत्र को डांट देते हैं कहते हैं जितना कहा है उतना करो। फिर भी आप इसी पुत्र से अपेक्षा करते हैं कि वह बढ़े होने पर चाय के साथ नाश्ता भी आपको दे।

क्या यह संभव है? उसको चाय के साथ नाश्ता देने के संस्कार आपने भरे कहां? इसीलिए बच्चों ने जो कुछ आपसे सीखा है वही व्यवहार आपके वृद्घ होने पर आपके साथ होगा। हमारा समाज हमारा देश बच्चों पर ही निर्भर है। इसीलिए बच्चों को अच्छे संस्कारों से सुसज्जित कर समाज और देश के विकास में सहयोग प्रदान करें।

ओडिशा की बाघिन "ज़ीनत" झारखंड के सिंहभूम के जंगलों में

लोगों में दहशत, झारखंड-ओडिशा के 90 कर्मी बाघ खोज में शामिल

कार्तिक परिच्छा, स्टेट हेड, झारखंड

जमशेदपुर। उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय रिजर्व पार्क से भटक कर आई बाघिन ₹ज़ीनत ₹ने झारखंड के पूर्वी सिंहभूम सिंहभूम जिले के चाकुलिया वन क्षेत्र के चियाबांधी जंगल में शरण ले रखी है. बुधवार को वन विभाग को सूचना मिली कि जीनत नाम की उक्त तीन वर्षीय बाघिन चियाबांधी के जंगल में छिपी हुई है. इससे पहले, मंगलवार को वह चाकुलिया शहरी क्षेत्र से कुछ किलोमीटर दूर गदरसोल के जंगल में पाई गई थी. बाघिन के गले में लगे रेडियो कॉलर और सेटेलाइट ट्रैकिंग के माध्यम से वन विभाग की टीम ने उसकी स्थिति का पता लगाने का प्रयास कर रही है । महाराष्ट्र तोडबा व्याघ्र प्रकल्प से विगत 24 नवम्बर लाई गयी 3 साल की बाघिन "जीनत" सिमलीपाल से सोमवार को फरार होने की सूचना ओडिशा वन विभाग एवं वाइल्ड लाइफ को हुई थी तब इसी खोजबीन आरंभ हुई जो आज झारखंड में पड़ाव पर है ।

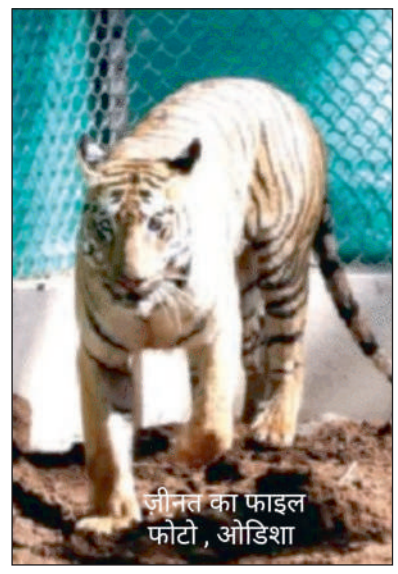

उधर बाघिन होने कारण अनेक स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं । लोग लोगों में भी दहशत व्याप्त है ।जंगल समीप गांव में शाम को लोग निकल नहीं रहे हैं।

बाघिन को पकड़ने के लिए उड़ीसा और झारखंड के 90 वनकर्मियों की टीम जुटी हुई है. बाघिन पिछले रविवार को गुड़ाबांदा थाना क्षेत्र में भटकते हुए पहुंची थी, और अब लगातार अपना स्थान बदल रही है. वन विभाग का मानना है कि बाघिन भूखी हो सकती है, क्योंकि उसे अब तक बड़ा शिकार नहीं मिला है. इसे पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा पिंजरा भी लगाया गया है और भैंस का भी इंतजाम किया गया है ताकि बाघिन को भोजन के रूप में आकर्षित किया जा सके.

ज़ीनत का फाइल फोटो, ओडिशा

उड़ीसा वाइल्डलाइफ के बीस कर्मी बाधिन पर नजर गड़ाए हुए हैं । झारखंड केचेकुलीया वन क्षेत्र एवं आसपास के 70 बनकर्मी बाघिन की घेराबंदी में लगे हुए हैं । कल इन वन कर्मियों ने बाघिन की जानकारी के बाद उन्होंने इलाके की घराबंदी कर लिया था । पर आज समाचार लिखे जाने तक उसकी कोई सूचना नहीं मिली है।

बॉलीबुड पर भारी पड़ी साऊथ इंडस्ट्री, 4 दिन में 800 करोड़, मतलब हर दिन दो सौ करोड़ : सावन चौहान

साऊथ सुपर स्टार अल्लू अर्जुन की फ़िल्मि पुष्पा 2 ने वो किया, जो अबतक कोई नहीं कर पाया : सावन चौहान

आगरा, संजय साग़र सिंह। पुष्पा 2' की ताबड़तोड़ कमाई से साऊथ एक्टर अल्लू अर्जुन ने ऐसा आंकड़ा पार किया है, जो अभी तक कोई इंडियन फिल्म कर ही नहीं पाई । इस मामले में अल्लू अर्जुन ने प्रभास जैसे टॉप स्टार्स को भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। ये इंडियन फिल्मों की कमाई के मामले में एक टॉप रिकॉर्ड बन गया है।

फ़िल्मि निर्माता सावन चौहान ने साऊथ इंडस्ट्री की बढ़ती ताकत और अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की सफलता पर उन्होंने कहा कि पुष्पा 2 ने चार दिन में 800 करोड़ की कमाई करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। वहीं, KGF 2, RRR, और बाहुबली 2 जैसी बड़ी फिल्मों से भी अधिक कमाई कर रही है, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। साऊथ फिल्म इंडस्ट्री, खासकर तेलुगु सिनेमा, दुनियां भर के दर्शकों को अच्छी फिल्मे दे रहा है। वहीं, अल्लू अर्जुन, प्रभास, राम चरण और जूनियर एनटीआर जैसे सितारे इंडस्ट्री में एक नई दिशा दिखा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे साऊथ इंडस्ट्री में नए स्टार्स के आने और बड़े बजट की एक्शन फिल्में बनाने से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने एक नई दिशा पकड़ी है, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आधारित है। इस बदलाव से यह स्पष्ट है कि साऊथ इंडस्ट्री का प्रभाव अब पूरे भारतीय सिनेमा पर बढ़ चुका है।

फ़िल्मि निर्माता सावन चौहान ने इंडियन फिल्मों की कमाई के मामले में एक टॉप रिकॉर्ड बनाने वाली पुष्पा 2 की तारीफ़ करते हुए कहा, ₹साऊथ सुपर स्टार अल्लू अर्जुन की फ़िल्मि पुष्पा 2 ने वो किया, जो अबतक कोई नहीं कर पाया। इस फ़िल्मि ने सिर्फ़ 4 दिन में 800 करोड़ यानी हर दिन दो सौ करोड़ कमाएं। इस शानदार कमाई से 'पुष्पा 2' ने KGF 2, RRR और 'बाहुबली 2' जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। 'पुष्पा 2' ने दुनिया भर में 'फायर' लगा दी हैं। वो अब वाइल्ड-फायर बन चुकी है। इस फ़िल्मि ने बॉक्स ऑफिस के सारे टॉप रिकॉर्ड राख कर दिए हैं।"

उन्होंने कहा, ₹साऊथ की यह फ़िल्मि फिल्मी इंडस्ट्री के बदलते परिप्रेक्ष्य और स्टार वैल्यू पर विचार करती है। हाल के समय में, पुष्पा 2 की अपार सफलता और उसके साथ-साथ अल्लू अर्जुन, प्रभास, राम चरण और जूनियर एनटीआर जैसे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सितारों के बढ़ते प्रभाव को प्रमुखता को दर्शाती है। वहीं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अब स्टार वैल्यू और सफलता का निर्धारण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म के व्यवसायिक परिणामों से होता है। 2003 के बाद बॉलीवुड में कॉर्पोरेट पैसे की बड़ी भूमिका बन गई है, जिससे स्टार्स की फीस और फिल्म के कारोबार में वृद्धि हुई है। पहले जैसे राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन की फीस सीमित थी, अब वही स्टार्स लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों की फीस लेते हैं लेकिन अब अल्लू अर्जुन जैसे सितारे भी 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं, और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने एक नई दिशा दिखाई है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से नए सितारे सामने आ रहे हैं जो अधिक प्रभावशाली साबित हो रहे हैं।₹

श्री चौहान ने आगे कहा,₹राजेश खन्ना को पहला सुपरस्टार माना गया, पर उसकी हाईएस्ट कीमत क्या थी 7 लाख से दस लाख रुपए। इसका रिकॉर्ड तोड़ा अमिताभ बच्चन ने जो 25 लाख तक पहुंचे बस। जैसे क्रिकेट में बेशुमार पैसा आईपीएल के बाद आया वैसे ही फिल्मों में पैसा हॉलीवुड के निर्माताओं और कॉर्पोरेट्स के आने के बाद यानी 2003 के बाद शुरू हुआ। फिल्मे अनाउंस हो जाने के बाद फिल्मों की रिलीज डेट तय कर दी जाती थी। इतना सिस्टमेटिक तरीके से काम होने लगा। गजनी पहली 100 करोड़ी फिल्म बनी और फिर करोड़ों का बिजनेस तीन चार दिन में तय कर स्टार की वेल्यू भी निकाली जाने लगी। इस हिसाब से फीस भी तय हो गई कि कौन कितनी जल्दी कितने ज्यादा दर्शक जुटाने की कुव्वत रखता है। यही काम बड़े बजट की फुल एक्शन मसाला मूवी बनाकर तेलगु फिल्म इंडस्ट्री कर रही है।

मर्द को दर्द नहीं होता…?

कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता?
रात को जाग कर भी वह नहीं सोता।
वह तो अतुल सुभाष था, ना वो रोता,
वह आखिर कब तक प्रताड़ना सहता!
अपना दर्द वह किस-किस को कहता।

कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता?
रात को जाग कर भी वह नहीं सोता।
इस कलयुग में क्या-क्या सेटल होता,
क्या? पुलिस, क्या? जज सबको देता!
इन लोगों के लिए सिर्फ एटीएम बनता।

कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता?
रात को जाग कर भी वह नहीं सोता।
क्या? अर्धांगिनी का मन भी ऐसा होता,
जो पवित्र रिश्ते को भी आग लगा देता!
माता-पिता को भी बिलखता छोड़ देता।

कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता?
रात को जाग कर भी वह नहीं सोता।
वह शिखर ही था जो मजबूर कर गया,
अपने कलेजे के टुकड़े को दूर कर गया!
सोचो, अतुल जिंदगी को निष्ठुर कर
गया।

संजय एम. तराणेकर

लालच का खेल

हर जगह जहाँ भी देखो,
दुनिया में लालच का खेल है
मतलब के इस जहाँ में,
सब लालच में अपने-आपको लगाए
हुए हैं।

दु:ख-तकलीफ़ में भी,
लोग अपना ईमान भूल गए
चंद पैसों की खातिर,
लालच के रंग में डूब गए।

अजब-गजब ज़िन्दगी के इस रंग में,
पैसे की भूख की खातिर
दो रोटी को भूल गए,
लालच के इस दौर में,
सब बदनाम हो इंसानियत भूल गए।

यह अंधेरा कुआं है जीवन में,
जिसमें रोशनी नहीं है।
क्योंकि लालच का यह पानी,
इसमें है
तभी तो यह सब लालची हो गए॥

हरिहर सिंह चौहान जबरी बाग़
नसिया इन्दौर मध्यप्रदेश

देश में बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार कौन?

(अंजनी सक्सेना-विभूति फीचर्स)

हमारे देश में रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के स्तर पर पहुंच चुके हैं। आम जरूरत की चीजों के दाम कम करने की कोई कोशिश भी दिखाई नहीं दे रही है। आज महंगाई की समस्या विकराल रुप धारण कर चुकी है। इसके भयंकर दूरगामी परिणाम होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं ऐसे में आज मंहगाई को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए । सरकारें महंगाई की समस्या को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखने की घोषणाएं तो करती हैं, किन्तु उन घोषणाओं के प्रति कोई भी सरकार गंभीर नहीं होती।

जब दाम बढ़ते हैं तो केवल अर्थव्यवस्था ही चौपट नहीं होती, सामाजिक नैतिक मूल्यों में भी ह्रास होता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की बढ़त अवरूद्ध होती है। देश की साख गिरती है। लोगों में योजना एवं सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता है। सामान्य सुविधाएं भी देश को नहीं मिल पाती, फिर कर्जों का बोझ और उसी अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता है। आज तक मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के तमाम प्रयास कमोवेश असफल साबित हुए हैं।

अतीत की बात करें तो कांग्रेस सरकार ने देश को आर्थिक संकट से उबारने का जो सरल रास्ता अपनाया था, वह देश के सामान्य जीवन के लिए कठिन चुनौती बन गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सलाह पर बनाई गई नीतियों से कुछ साधन एवं सत्ता संपन्न लोगों को छोड़कर जनता की आमदनी में कोई वृद्धि नहीं हुई।

आज यह समस्या देश की स्थायी समस्या बन गयी। पानी, बिजली, मकान पर लगने वाले कर, कपड़ा एवं यातायात 25 प्रतिशत से 1000 प्रतिशत तक महंगे हो गए हैं । इसी बीच डीजल, पेट्रोल, रसोई-गैस, कोयला व इस्पात सबके भाव बढ़े तो व्यापारियों ने भी मनमानी वृद्धि कर दी। कीमतों की यह बढ़ोत्तरी किसी एक क्षेत्र में नहीं हुई है, बल्कि यह बढ़ोत्तरी करीब-करीब सभी क्षेत्रों में हुई है। सबसे अधिक बढ़ोत्तरी तो आम लोगों की जरूरत वाली चीजों के प्राथमिक क्षेत्र में हुई है। अगर थोक मूल्यों का सूचकांक ही लें, तो सबसे अधिक बढ़ोत्तरी फलों, सब्जियों और अनाजों के दामों में हुई । इनकी कीमतों में भी कई गुना बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। अरहर और उड़द जैसी अधिक खाई जाने वाली दालों के दाम तो हर साल आसमान छूने लगते हैं। जबकि चावल के दामों की भी लगभग यही स्थिति है। कुल मिलाकर भोजन की वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है।

खाने की वस्तुओं के दामों में उतार-चढ़ाव होते रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मगर अच्छी वर्षा होने के कारण खाने की वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आनी चाहिए पर इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस स्थिति को गंभीर बनाने वाली बात यही है कि बाकी सभी क्षेत्रों में भी दाम आज भी बढ़ रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि बाजार दबाव में है। महंगाई अर्थव्यवस्था में पैदा होने वाले नये-नये संकटों की एक सरलीकृत अभिव्यक्ति है, इसलिए महंगाई बढ़ाने की जिम्मेदार शक्ति केन्द्र सरकार है, जो समूची अर्थव्यवस्था का नियंत्रक है। हमारी अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण है? आयात-निर्यात नीति कौन तय करता है? उत्पाद कर निर्धारण कहां से होता है? अप्रत्यक्ष करों का जाल कौन बिछाता है? नमक से लेकर आयतित विमान के मूल्य निर्धारण का अधिकार किसके हाथ में है? इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है- केन्द्र सरकार। हमारे देश में जो व्यवस्था लागू हैं, उसमें वस्तुओं की चाहे वे देश में उत्पादित हों या विदेश से आयातित कीमत निर्धारित करने और कीमत घटाने बढ़ाने का विशेषाधिकार केंद्र सरकार को ही प्राप्त है, अतः महंगाई बढ़ाने का अपराध भी यही करती है। पूंजीपति, मुनाफाखोर,

जमाखोर व बिचौलिया व्यापारी अधिक से अधिक सह-अपराधी की भूमिका निभा सकते हैं।

यह भी एक विडम्बना ही है कि जो मूल्य वृद्धि का असली खलनायक है, उसे ही जनता भ्रमवश जब तब त्राता के रूप में देखती है। महंगाई की सुरसा अपना बदन बढ़ाती चली जाती है। सरकार भी जनता को खुशफहमी में डालने के लिए ममतामयी छवि का रूप धारण करती है। महंगाई के विरुद्ध युद्ध का स्वांग भरा जाता है, लेकिन इस युद्ध में सरकार अपनी चतुराई से महंगाई रूपी सुरसा से पार पाने में नहीं, अपितु जनता को मूढ़ साबित करने में सफल हो जाती है। महंगाई की सुरसा ज्यों की त्यों बनी रहती है। जनता इसके बाद दूसरी सरकार को आजमाती है। अब तो स्थिति यह है कि महंगाई चाहे कितनी बढ़ जाये, वह कोई सनसनीखेज मुद्दा नहीं बन पाती।

महंगाई की चर्चा शुरू होते ही अर्थ जगत के कुछ मिथकीय चरित्र अपने विशालकाय दानवी रूप में हमारी कल्पना में उभरने लगते हैं। हम अपनी कल्पना की रौ में ही मुनाफाखोर, जमाखोर, पूंजीपति और व्यवस्था को कोसने लगते हैं। ऐसा करते हुए हमें आभास होता है कि हम सामाजिक चेतना से परिपूर्ण हैं। यह ऐसी खुशफहमी हैं, जो हमें महंगाई के कटु यथार्थ को मीठे दर्द की तरह झेल जाने का माद्दा दे जाती है। प्रचलित मिथकों में से एक यह भी है कि महंगाई इजारेदार पूंजीपति व बड़े व्यापारी बढ़ाते हैं। चुनाव में सरमायेदार व व्यापारी राजनीतिक दलों को भारी चन्दा देते हैं और बदले में जिंसों की मनमानी कीमत बढ़ा लेते हैं। एक भ्रम यह भी है कि देश में स्थापित समानांतर अर्थव्यवस्था के कारण महंगाई बढ़ती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सत्ता में रहने के दौरान इस भ्रम को खूब पुख्ता किया था। चन्द्रशेखर ने अपने संक्षिप्त प्रधानमंत्रित्व काल में एक अस्थायी मिथक गढने की कोशिश की और महंगाई को खाड़ी युद्ध की देन बताना शुरू किया था। इन सबसे भिन्न कुछ ऐसे लोग हैं, जो बड़े सात्विक भाव से कहते हैं कि महंगाई बढना एक सामान्य विश्वव्यापी समस्या है और हमारे देश को इस पर अलग से चिन्तित होने की जरूरत नहीं है। सीमाहीन झूठ का इससे अच्छा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता, जिसे हमारी अब तक की सरकारें किसी न किसी रूप में प्रकट करती रहीं है।

कीमतों की वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक स्थायी समस्या बन चुकी है। यदि महंगाई के अनुपात में ही लोगों की वास्तविक आय बढ़ती रहे तो चिंता की बात नहीं होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। महंगाई का कहर सब पर समान रूप से टूटता है, किन्तु कुछ लोगों की आय तेजी से बढ़ती है और ज्यादातर लोगों की आय स्थिर रहती है या उसमें बहुत मामूली इजाफा होता है। ऐसी स्थिति में इसी पर आश्चर्य होता है कि महंगाई का सवाल हमारी राजनीति के केन्द्र में क्यों नहीं आ पाया है। क्रय शक्ति बढ़ाने के लिये जरूरी है- आय में वृद्धि होना। जो रोजगार, कारोबार में है, वे अपनी आय ज्यादा बढ़ा लेते हैं। वेतनभोगी वर्ग, सांसद, विधायक सभी दबाव डालकर अपने वेतन बढ़वा लेते हैं। किंतु देश में 75 प्रतिशत वेतनभोगी प्राइवेट कर्मचारी व खेतों में काम करने वाले मजदूर भी हैं। अगर आय ज्यादा न बढ़े, लेकिन उत्पादन आबादी के हिसाब से बढ़े तो भी महंगाई नियंत्रित रहती है, किन्तु जब देश की आय का अधिकांश हिस्सा कर्ज अदायगी में जायेगा, आय से अधिक खर्च की सरकारी नीति रहेगी, मुफ्त का धन और राशन बांटने की वोट उगाऊ राजनीति रहेगी, उद्योगों में पश्चिमी देशों का अन्धानुकरण होगा, तो हर हाथ को काम व रोजी-रोटी मिलना भी मुश्किल है।

आमतौर से केन्द्र सरकार की आर्थिक ताकत का अंदाजा लोगों को कम ही है। आयात-निर्यात पर जो किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है, पूरी तरह केन्द्र सरकार का नियंत्रण है। सारे औद्योगिक उत्पादनों के लागत मूल्यों पर न्यूनतम 100 प्रतिशत से लेकर 300 प्रतिशत तक मुनाफे के साथ उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है और इन उत्पादनों पर होने वाले कुल लाभ का विभिन्न टैक्सों के माध्यम से 80 प्रतिशत अंश सरकार हड़प लेती है। जनता पर प्रत्यक्ष व परोक्ष कर ज्यादातर केन्द्र सरकार ही लगाती है। इसके बावजूद वह लाचार व निरीह बनकर महंगाई बढने की जिम्मेदारी यहां वहां डालने का प्रयास करें तो कोई क्या कर सकता है? भ्रम की स्थिति उस समय तक बनी रहेगी, जब तक महंगाई की समस्या को राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में नहीं देखा जायेगा। (विभूति फीचर्स)

पूर्व डीएम छवि रंजन का वेल पिटिशन रांची मे खारीज

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

रांची, नेताओं चहेते बने रहने की ललक के लिए सरायकेला - खरसावां में जमीन कारोबार से सीधे रांची के डीसी बने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छवि रंजन को पी एम एल ए के न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत से आज निराश होना पड़ा है । चेशायर होम रोड की ज़मीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़े लैंड स्कैम केस के आरो छवि रंजन की डिस्चार्ज पिटीशन राँची पी एम एल ए (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लॉनड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी है. सोमवार को सभी पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. इस मामले में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने बहस की. दरअसल रांची के बड़गाईं अंचल के चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ईडी रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया था. सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल भी हो चुकी है.

अमरदा एयर पोर्ट होगा की नहीं होगा साधारण लोगों की मन में आशंका

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: ऐतिहासि अमरदा हवाई मयूरभंज जिले के रसगोबिंदपुर में स्थित है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1940 में स्थापित यह हवाई क्षेत्र 1943 में वायु सेना प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा था। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ चीनी राष्ट्रवादी सेना के लिए और अमेरिकी वायु सेना के लिए अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी तिब्बत के माध्यम से चीन तक पहुंचने के लिए परिवहन प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया।

लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वीरान पड़े इस हवाई क्षेत्र के जीर्णोद्धार के लिए तत्कालीन मंत्री बिस्वेश्वर टुडू के प्रयास से 160 पर इसे वाणिज्यिक हवाई क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सुरक्षा विभाग और भारत सरकार से अनुमति मिल गई। २६ करोड़ रुपये के बदले एक एकड़ जमीन. यदि अधुना लागू किया जाता है, तो बारीपदा मेडिकल कॉलेज, पर्यटक केंद्र दीघा और हावड़ा रेलवे स्टेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। इसके महत्व को स्वीकार करते हुए, वर्तमान राज्य वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने इस क्षेत्र के विकास की घोषणा की है और घोषणा की है कि यह जल्द ही चालू हो जाएगा।

लेकिन यह खेद और विवाद का विषय है, जबकि अरमाडा हवाई अड्डा चालू नहीं है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुर में डांडबोस हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है, इस शिलान्यास के बाद, वैधता के बारे में जनता के बीच संदेह व्यक्त किया गया है। एक जिले में दो हवाई अड्डों की और कार्यक्षमता। विशेष रूप से अमरदा हवाई अड्डे का भविष्य अंधकार में डाल दिया गया है। पूर्व केंद्रमंत्री बिस्वेश्वर टुडू का प्रचेस्टा बेकर ना जाए ।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। **RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023**